कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

आवरण कथा :

छत्तीसगढ़ विकास यात्रा 2013 7

संसद में बहस : किस्तवाड़ में हिंसा

अरुण जेटली, राज्यसभा में विपक्ष के नेता..... 9

लेख

खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों
– **नितिन गडकरी**..... 12

मृत्यु शैया पर पड़े रोगी जैसी दशा
– **यशवंत सिन्हा**..... 14

कांग्रेस को नहीं दिखती जिहादी साजिश
– **बलबीर पुंज**..... 16

हर मोर्चे पर विफल सरकार
– **ए. सूर्यप्रकाश**..... 19

विशेष साक्षात्कार

जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा..... 21

अन्य

दिल्ली : रामलीला मैदान में बिजली रैली..... 24
आंध्र प्रदेश : 'नवभारत युवाभेरी'..... 26
मध्य प्रदेश : जन–आशीर्वाद यात्रा..... 28

मुख पृष्ठ : *छत्तीसगढ़ विकास यात्रा*

कमल संदेश के सभी पाठकों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!

सिर्फ प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता

एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के सत्संग के लिए अक्सर आया करता था। वह बहुत उत्सुकता से उनके उपदेश सुना करता। बुद्ध उपदेश में प्राय: कहते, लोभ, दोष और मोह पाप के मूल हैं। हिंसा करना और असत्य बोलना अधर्म है। यदि सच्ची शांति चाहते हो, तो इन दुर्गुणों को त्याग दो। क्रोध करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता।

वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के उपदेश तो सुनता, लेकिन दुर्गुणों को त्याग नहीं पा रहा था। हर क्षण उसका मन अशांत रहता था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवन, मैं काफी दिनों से आपका उपदेश सुनता आ रहा हूं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ा। मन बड़ा अशांत रहता है।

बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, तुम कहां के रहनेवाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला सवाल किया, यहां से श्रावस्ती कितनी दूर है? व्यक्ति ने दूरी बता दी, तो बुद्ध ने उससे फिर पूछा, तुम अपना रास्ता जानते हो? उसने कहा, खूब अच्छी तरह। तब भगवान बुद्ध ने पूछा, रास्ता जानने के बाद उस पर चले बिना क्या तुम श्रावस्ती पहुंच सकते हो? उसने उत्तर दिया, वहां पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा।

बुद्ध ने तब फिर कहा, वत्स, सिर्फ प्रवचन सुनने या कल्याण का मार्ग जानने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उस पर चलना पड़ेगा। उन्हें अपने आचरण में ढालो, फिर देखना कि किस तरह तुम्हारा मन शांति का अनुभव करता है।

ऐसा करने पर उसका स्वत: कल्याण हो गया।

– शिवकुमार गोयल
(अमर उजाला से साभार)

व्यंग्य चित्र

गुम फाइलों ने बेनकाब किया कांग्रेस का खेल

कोयला घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों का गुम होना चिंताजनक है। इन फाइलों का गुम होना यह दर्शाता है कि बहुत जल्दी जनता यूपीए की फाइल को गुम कर देगी। गैर-जिम्मेदाराना सरकार की इससे बड़ी हरकत क्या हो सकती है? वह चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी। भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले (कोयले की दलाली) में पूरी यूपीए सरकार डूबी हुई है। जो फाइलें गायब हुई हैं, वो कांग्रेस से जुड़े लोगों से संबंधित हैं। यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के चेहरे पर कोयले की कालिख पुती हुई है। अगर ये फाइलें गुम नहीं होती तो श्री ए. राजा की तरह ये तीनों भी हिरासत में होते। सुना गया है कि इन फाइलों में श्रीमती सोनिया गांधी के निजी सचिव श्री अहमद पटेल की लिखी पर्चियां हैं।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब होने के मुद्दे को लेकर भाजपा ने संसद के दोनों सदनों में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय रहा था, इसलिए संबंधित व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं। पीएम पूर्व में इस बारे में सदन को आश्वस्त कर चुके हैं, लेकिन फाइलें गायब हैं। इसलिए, वह सदन को बताएं कि फाइलें कहां और कैसे गायब हुई। अब कैसे वापस आएंगी? वहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि फाइलें गायब नहीं होती, उन्हें गायब कराया जाता है।

जबसे कांग्रेसनीत यूपीए सरकार सत्ता में आई है तबसे वह लगातार एक के बाद एक बड़े घोटाले को अंजाम देती जा रही है। इस सरकार के शासन में इतने घोटाले हुए हैं कि सबको याद रखना भी मुश्किल है। लेकिन कोयला घोटाला ने तो पूर्व के सारे घोटालों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कोल आवंटन में बेहिसाब धांधली हुई। कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। किस आधार पर खदान आवंटित किए गए, यह भी एक रहस्य ही है। लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, वह तो हुए ही, साथ ही कई जरूरी फाइलें भी गुम कर दी गईं। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार कोलगेट में पूरी तरह बेनकाब हो गई है। लेकिन फिर भी वह बड़ी बेशर्मी से घटिया स्तर पर उतर कर लीपापोती करने में जुटी हुई है।

कहावत है कि कोयले की दलाली में मुंह काला होता है। सच में पूरी सरकार पर कालिख पुत गई है। आज संसद से लेकर सड़क तक कोयले से पुती यूपीए के कालिख की चर्चा हो रही है। लोगों में आक्रोश है। यूपीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

आज भारत के लोगों को केन्द्र में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की काली करतूतों का पता चल चुका है। देश गहरे आक्रोश और पीड़ा से भरा पड़ा है। अब वह बैलेट के जरिए अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता है। पूरा देश भाजपा की ओर आशा की नजरों से देख रहा है। यह बात मात्र घोटालों की संख्या तक ही सीमित नहीं है बल्कि महंगाई नियंत्रण न कर पाना और अर्थव्यवस्था की बदइंतजामी भी इसमें शामिल है। आज जब देश में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था की देखभाल कर रहा हो, ऐसे समय में देश की अर्थव्यवस्था दुर्दशा और बदहाली में पड़ी हुई है। अब लोगों को श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की याद आती है। वे उन दिनों की स्थिर मूल्य व्यवस्था, वाइब्रेंट इकॉनामी को नहीं भूले हैं जिसमें भविष्य की आशाएं थीं और वह युग था एक मजबूत और स्थिर रुपए का। वह युग था विकास का और सुशासन का, वह युग था विश्वास से भरपूर अर्थव्यवस्था का। कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था की संभावनाएं तबाह करके रख दी है और इसके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को अधम स्थिति में पहुंचा दिया है। लगभग सभी रेटिंग एजेंसियों ने हमारी

अर्थव्यवस्था को डाउनग्रेड कर दिया है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य नेतृत्व में जितनी बढ़त मिली थी, उसे खो दिया है। इसके लिए जिम्मेदार है कौन? अब कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार अपनी काली करतूतों, कुशासन और बदइंतजामी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।

कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार विदेश मोर्चे पर भी विफल रही है। आज तो चीन और पाकिस्तान से घुसपैठ आए दिन की बात बन कर रह गई हैं। सरकार को नियंत्रण रेखा पर हमारे जवानों की हत्याओं की जरा फिक्र नहीं है और वह उस समय भी मूक दर्शक बनी रहती है जब शत्रु हमारे जवानों के सिर घड़ से अलग कर देते हैं। यह एक ऐसी दब्बू और बिना रीढ़ वाली सरकार है जो कभी भी सीमापार से मिली चुनौतियों का जवाब देना ही नहीं जानती। बिडंबना यह है कि जले पर नमक छिड़कने के लिए इसके मंत्रीगण घुसपैठियों को सबक सिखाने की बजाए बे-सिर-पैर के बयान देते रहते हैं।

अब तो कांग्रेस-नीत यूपीए के दिन गिन-गिनाए रह गए हैं। लोग उस अवसर का इंतजार कर रहे हैं जब वे इस सरकार को सदा के लिए कूड़ेदान में डाल देंगे। भाजपा को लोगों की इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभानी है। भाजपा को लोगों के इच्छाओं के अनुरूप चलना है ताकि कांग्रेस-मुक्त भारत का सपना साकार हो जाए। जब तक कांग्रेस को सत्ता से हटाया नहीं जाएगा तब तक भारत की प्रगति और उसे विश्व के राष्ट्रों में अपना सही स्थान दिलाना संभव नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस भ्रष्टाचार और पारिवारिक राजनीति की एक सड़ी-गली पार्टी बनकर रह गई है। आज यह लोकतंत्र की व्यवस्था के लायक ही नहीं रह गई है और यह भारत को विकास की ओर ले जाने में अक्षम है। अत: अब सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कमर कसनी होगी और भारत को एक समृद्ध, मजबूत, आत्मनिर्भर और महान् राष्ट्र बनाने के लिए अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने का संकल्प लेना होगा। ■

पीस पार्टी के महासचिव भाजपा में शामिल
इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है भाजपा : राजनाथ सिंह

देश में परिवर्तन का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों व भाजपा शासित राज्यों में हो रहे सर्वसमाज के सर्वांगीण विकास और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज की बेहतर स्थिति को देखते हुए, डॉ. एम.जे. खान मुख्य संपादक एग्रीकल्चर टुडे व राष्ट्रीय महासचिव पीस पार्टी अपने 200 पदाधिकारियों व समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने सदस्यता ग्रहण कराई। पार्टी में शामिल होने वालों में श्री सुनील चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश); श्री सुधीर त्यागी, प्रदेश महासचिव; श्री परवेज़ आलम, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद; श्री शमीम अहमद, प्रदेश सचिव; श्री हरीश त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महान दल; डॉ. मुख्तार आलम, कार्यकारी निदेशक, कृषि एवं ग्रामीण विकास केन्द्र तथा इनके साथ करीब एक दर्जन जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख व कई गांवों के ग्राम प्रधानों ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा जाति, मजहब व सम्प्रदाय की कभी राजनीति नहीं करती। उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काल के दौरान सिर्फ इंसाफ व इंसानियत की बुनियाद पर ही फैसले हुए। आज भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा व गुजरात में मुसलमान अपने को सबसे सुरक्षित मानता है व हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना है, जिसके साठ साल की हुकूमत में मुसलमान जिंदगी के हर पहलू पर पिछड़ता कैसे चला गया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी ने 272 से अधिक सीटें जीतने का जो लक्ष्य कल निर्धारित किया है, उसमें सभी वर्ग के युवाओं को विशेषकर मुस्लिम युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। आज डॉ. एम.जे. खान का पार्टी में शामिल होना पार्टी के इस अभियान को तेजी से चलाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

डॉ. एम.जे. खान अंतर्राष्ट्रीय कृषि सलाहकार समूह (आई.ए.सी.जी) व पूरे देशभर के किसान संगठनों के राष्ट्रीय फेडरेशन (फीफो) के अध्यक्ष के साथ-साथ मुसलमानों की सर्वोच्च संस्था इंडियन मुस्लिम रिसर्च एंड कोर्डिनेशन सेंटर (आई.एम.आर.सी.) के राष्ट्रीय संयोजक है। डॉ. खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमबीए व प्रेसकॉट यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से कृषि प्रबंधन में पीएचडी है। अध्यक्ष जी ने भरोसा जताया कि डॉ. खान अब पार्टी में आकर न पार्टी के सिर्फ किसान एजेंडा को मजबूती से देश की राजनीति के केन्द्र बिन्दु में रखेंगे और सभी किसान संगठनों को अपने साथ खड़ा करेगें बल्कि देश के मुस्लिम बुद्धिजीवी, समुदाय केतमाम संगठन व विशेषकर मुस्लिम युवाओं को तेजी से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने में विशेष भूमिका निभाएंगे। ■

करोड़ों गरीबों के हित में केन्द्र को अपनाना चाहिए छत्तीसगढ़ का खाद्य सुरक्षा कानून : सुषमा स्वराज

संवाददाता द्वारा

वरिष्ठ भाजपा नेता व लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा है कि केन्द्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा कानून को जस का तस अपना ले तो देश के करोड़ों गरीब परिवारों को भूख की चिन्ता से मुक्ति मिल सकती है और केन्द्र का प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में एक घण्टे के भीतर सर्वसम्मति से पारित हो सकता है और एक बेहतर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बन सकता है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर, किसानों से धान खरीदी की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था, समुचित भण्डारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक बेहतर नेटवर्क तैयार करके देश का पहला खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून बनाया है। ऐसा करके छत्तीसगढ़ ने केन्द्र सहित भारत के सभी राज्यों को एक ऐसी प्रेरणा दी है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति और अंतिम घर तक खुशहाली आ सकती है।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने 19 अगस्त 2013 को रायपुर जिले के विकासखण्ड मुख्यालय आरंग में राज्य सरकार की प्रदेश व्यापी विकास यात्रा का शुभारंभ करते हुए एक विशाल जनसभा में इस आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रायपुर जिले की इस विकास यात्रा के रथ को हरी झण्डी दिखाकर आरंग से नवापारा, अभनपुर, बोरियाकला, माना बस्ती और माना कैम्प के लिए रवाना किया। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच आज रायपुर जिले की विकास यात्रा में जनता के लिए अरबों रूपयों की सौगातों की बौछार हुई। आरंग सहित इन सभी स्थानों पर विकास यात्रा की विशाल जनसभाओं में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज लगभग 893 करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन कर जनता को विकास की नयी सौगातें दी।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आरंग क्षेत्र की जनता को लगभग 106 करोड़ 26 लाख रूपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देकर उनका लोकार्पण और भूमिपूजन किया। 110 परिवारों को नवनिर्मित मकानों का अधिकार पत्र भी सौपा। जिले की एक दिवसीय विकास यात्रा का शुभारंभ आरंग में लोकसभा की नेताप्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया। मूसलाधार बारिश के बीच वे दोपहर विशेष विमान से रायपुर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।

बारिश से भीगे खुशनुमा माहौल में हजारों की संख्या में लोगों ने श्रीमती सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री का जोशीला स्वागत किया। विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ ने विगत लगभग

साढ़े नौ साल में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कीर्तिमान बनाए हैं, जिनकी चर्चा आज सारे देश में हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ को जन कल्याण की अपनी योजनाओं के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में पहचाना जा रहा है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जिसे डॉ. रमन सिंह के कुशल नेतृत्व में गरीबों के लिए देश का पहला खाद्य सुरक्षा कानून बनाने का श्रेय मिला है। गरीबों की भलाई के लिए बने छत्तीसगढ़ के इस कानून की चर्चा आज देश-विदेश में हो रही है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि केन्द्र सरकार देश के करोड़ों गरीबों के भलाई के लिए अगर छत्तीसगढ़ का खाद्य सुरक्षा कानून अपना ले, तो केन्द्र का प्रस्तावित विधेयक निश्चित रूप से एक घंटे के भीतर संसद में सर्वसम्मति से पारित हो सकता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि आज भारत के करोड़ों गरीबों की तरक्की और खुशहाली तथा राष्ट्र के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य के रूप में देखा जा रहा है, जहां गांव, गरीब और किसानों तथा समाज के सभी वर्गों के लिए मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें अमलीजामा भी पहनाया है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि नक्सल हिंसा को खत्म करने के लिए भी छत्तीसगढ़ ने डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में पूरी दृढ़ता के साथ मोर्चा संभाला है और प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण विकास तथा कानून व्यवस्था दोनों ही मोर्चे पर राज्य सरकार संकल्प शक्ति के साथ काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने भी इस अवसर पर राज्य की जनता की ओर से श्रीमती सुषमा स्वराज का स्वागत करते हुए विशाल जनसभा को सम्बोधित किया।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्षेत्रीय असंतुलन और पिछड़ेपन की पीड़ा से जनता को मुक्ति दिलाने और बस्तर से सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ को सुशासन और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वर्ष 2000 में नये राज्य का निर्माण किया था। अटल जी ने जिन सपनों की बुनियाद पर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया आज यह नया प्रदेश अपनी दो करोड़ 55 लाख जनता के सहयोग से उन तमाम सपनों को तेजी से साकार कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2003 से 2013 के बीच अब तक छत्तीसगढ़ ने अपनी मेहनतकश जनता के सहयोग से हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ अब तेरह साल का किशोर बन चुका है। तेरह वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था तेज विकास की होती है। छत्तीसगढ़ के लिए यह पांच साल का आने वाला समय विकास के स्वर्णिम युग के रूप में होगा। यह देश के सर्वाधिक विकसित गिने-चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का एक मात्र एजेण्डा केवल राज्य का विकास और जनता की भलाई के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार दिल की गहराईयों से सोचकर नीति और योजनाएं बनाती है। विगत साढ़े नौ साल में छत्तीसगढ़ में समाज का कोई भी वर्ग और राज्य का कोई भी कोना विकास के मामल में अछूता नहीं रह गया है। हमने हर क्षेत्र में विकास की रोशनी पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है और जनता के सहयोग से इसमें अच्छी सफलता भी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जाति और वर्ग भेद की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर प्रदेश के गरीबों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने अपने खाद्य सुरक्षा कानून में 42 लाख गरीब परिवारों और लगभग दस लाख सामान्य परिवारों को भी शामिल किया है, जिन्हें रियायती दर पर पर्याप्त अनाज की गारंटी दी गयी है। गरीब परिवारों को इस कानून के तहत मात्र एक रूपए और दो रूपए किलो में हर महीने 35 किलो अनाज, आदिवासी क्षेत्रों में मात्र पांच रूपए किलो में दो किलो चना और गैर आदिवासी क्षेत्रों में मात्र दस रूपए किलो में दो किलो दाल देने की व्यवस्था की गयी है। उनके लिए दो किलो नमक नि:शुल्क दिया जा रहा है।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी श्री जगत प्रकाश नड्डा, खाद्य मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी श्री पुन्नूलाल मोहले, स्कूल शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत, कृषि मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री रमेश बैस, और डॉ. भूषण लाल जागड़े, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष श्री अशोक बजाज, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री सुभाष राव तथा जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ■

किश्तवाड़ की घटनाएं भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता का प्रश्न है

महोदय, मैं आपके प्रति अत्यंत आभार प्रगट करता हूं कि आपने मुझे इस देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा उठाने के लिए अनुमति प्रदान की। यह वह मुद्दा है जो न केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के दो सम्प्रदायों के बीच सम्बन्धों के बारे में है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता का प्रश्न है।

महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं 23 वर्ष पूर्व हुई। वे एक सम्प्रदाय को चुन-चुनकर निशाना बना रहे थे। यह विशाल आंदोलन में बदल गया और एक सम्प्रदाय को कश्मीर घाटी छोड़ कर जाना पड़ा। हम आज भी इन घटनाओं और गहरा दु:ख महसूस करते हैं। यह देश यथा पूर्व स्थिति बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उन लोगों को वापस भेजना चाहता है, परन्तु हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। परन्तु, दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ महीनों में घाटी के अन्दर की, जहां तक आतंकवाद का सम्बन्ध है, थोड़ी बहुत हालत सुधरी है और हम सभी इससे प्रोत्साहित हुए हैं।

हम चाहते हैं कि यह स्थिति और भी सुधरे ताकि तनाव की स्थिति में जो राष्ट्र विरोधी तत्व लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और इसे प्राप्त भी कर लेते हैं, वे इसका लाभ न उठा सकें। अभी कुछ दिन पूर्व, एक बात और हुई, माननीय रक्षामंत्री ने एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि नियंत्रण रेखा की सीमा पार से तनाव बढ़ रहा है और घुसपैठ बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि हालांकि घाटी में पहले की

12 अगस्त 2013 को राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड में हुई साम्प्रदायिक झड़पों का मुद्दा उठाया। यहां उनके भाषण के प्रमुख अंश प्रस्तुत है:

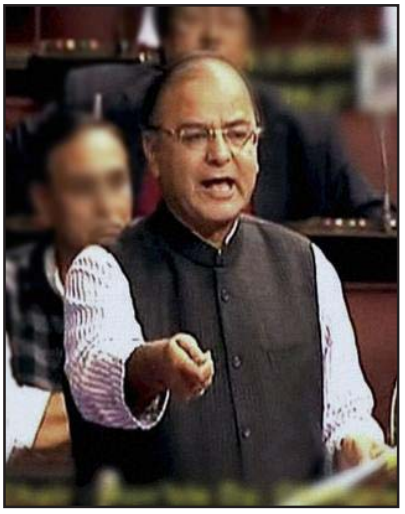

अपेक्षा शांति है, फिर भी जम्मू के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां चल रही है, जो हाल की घटी घटनाओं से पहले भी गहन चिंता का विषय रही है। अब, किश्तवाड़ में मिली-जुली आबादी है, जैसा कि इस क्षेत्र के अधिकांश जिलों में कुछ ऐसा ही है। ऐतिहासिक रूप से इन जिलों में साम्प्रदायिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं। समुदायों आदि के बीच तनाव कभी-कभी ही देखने को मिलते हैं।

तनाव के कुछ दृष्टांत थे। पांच वर्ष पूर्व अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ घटनाएं हुई परन्तु वह थोड़े समय तक ही रहीं। और अन्त में, स्थिति में भी सुधार हुआ। विगत कुछ दिनों में, किश्तवाड़ में अनेक राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हुई, जो अन्यथा एक शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है, परन्तु अब ये बढ़ गई हैं। ईद के पवित्र त्योहार पर कुछ घटनाओं के कारण विरोध और प्रदर्शन हुए और जो कुछ वहां हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए जिसमें कुछ चुने लोगों को विशल बनाया गया और चुने लोगों को निशाना बनाने का काम शुरू हुआ तो इस बारे में भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर ध्यान खींचा गया। इन घटनाओं के घटने के बाद लगभग कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री से बात हुई क्योंकि 1990 और 2013 के बीच काफी बड़ा अन्तर है (लोग मोबाईल से बात पहुंचाते हैं)। अब, ट्विट ई-मेल भी संचार का साधन बन गया है। और, कुछ ही मिनिटों में, बात दिल्ली तक पहुंच जाती है कि वहां क्या घटनाएं घटी होती हैं। लोग अपनी लाचारी से कराह रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसी शिकायतें और भी है कि राज्य सरकार के बड़े अधिकारी भी इनमें संलिप्त थे और यह ऐसा मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले का पता लगने के बाद तुरन्त ही इसे सरकार के उच्चतम स्तर, माननीय प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया गया। दोपहर से पूर्व ही हमें बताया गया कि स्थिति तनावपूर्ण है और सेना को मोर्चे पर भेजा जा रहा है। जिसने भी हमसे

सम्पर्क किया, हम उन सभी व्यक्तियों को बताते रहे कि सेना भेज दी गई है और उम्मीद है कि स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। जिले के सभी अधिकारी चाहे जिला मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो या एसएसपी हो, सभी इस स्थिति के दर्शक थे। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कल शाम की बात है, अर्थात् घटना होने के तीन दिन बाद आप देख रहे हैं कि हजारों दुकानों को आग लगा दी गई, घरों को लूटा गया और दर्जनों लोग घायल हो गए। उनका सिविल हस्पताल में इलाज तक नहीं हुआ- इस हद तक तनाव था और उन्हें आर्मी हस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसा भी हुआ है कि आपने देखा कि बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। स्थिति को तुरंत ही काबू में लाया जाना चाहिए था। परन्तु, अगले कुछ घण्टों में, जब हम बात कर रहे थे तो भारत सरकार ने विश्वास दिलाया कि सेना को भेजा जा रहा है, मैं अवश्य समझता हूं कि गृह और रक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई की शुरूआत की और कहा कि सेना वहां पहुंच जानी चाहिए, परन्तु कल देर रात ही सेना पहुंची, जबकि सेना वहां नजदीक ही तैनात थी, और वह मोर्चे पर डटी। और इन छह घण्टों में, किश्तवाड़ में नरसंहार हुआ और स्पष्ट है कि जब आज की संचार प्रणाली में बातें जल्द पहुंच जाती है तो इसके कारण पड़ोसी क्षेत्रों में भी तनाव पैदा हुआ। मैं इतना अवश्य समझता हूं कि दो सम्बन्धित अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और एस एस पी को अपनी ड्यूटी न निभाने के कारण निकाल बाहर करना चाहिए था। बीएसपी के एक मित्र की शिकायत है कि दुर्भाग्य से उनके जिला अध्यक्ष का बेटा मारा गया। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ औरों के साथ भी हुआ होगा। हम उनके साथ सहानुभूति प्रगट करते हैं।

मेरे साथ जो कुछ हुआ, उसे मैं एकदम गौण मानता हूं। परन्तु, आपको इतना जरूर बता दूं, महोदय, इस मामले में भी, जम्मू और कश्मीर राज्य किसी एक परिवार की निजी सम्पत्ति नहीं है। यह भारत का अभिन्न अंग है। और, आपको निर्णय करना होगा कि इस पर कैसे शासन किया जाए। कोई डेढ़ वर्ष पूर्व, मैं और लोकसभा से मेरी सहयोगी श्रीमती सुषमा स्वराज वहां थीं। मैं श्री चिदम्बरम की कानूनी प्रवीणता का सम्मान करता हूं, फिर भी उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। अब, राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगाने के लिए धारा 144 का सहारा लिया गया। हम वहां किस लिए जा रहे थे? हम जम्मू में एक रैली को सम्बोधित करना चाहते थे जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना था।

अब, हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें सेंसरशिप लगा देनी चाहिए, ताकि किसी को कुछ पता ही न चले? क्या हम शुतुरमुर्गी दृष्टिकोण अपनाएं कि मीडिया को उन इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी जाए। मुझे याद है, महोदय, जब अमरनाथ यात्रा आन्दोलन चल रहा था, और जम्मू क्षेत्र और घाटी दोनों क्षेत्रों में ही विशाल विरोध-प्रदर्शन हुए, तब श्री शिवराज पाटिल संसद सदस्यों का एक शिष्टमण्डल लेकर वहां गए थे। हम दोनों क्षेत्रों में गए, हमने लोगों के दिमागों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद, जब पथराव शुरू हुआ, श्री चिदम्बरम सर्वदलीय शिष्टमण्डल लेकर गए जिसने हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश की ताकि लोग अपना गुस्सा खत्म करें। और अब ऐसा दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं- जिसमें राज्य की घटनाओं पर पर्दा डाला जा रहा है (किसी को भी राज्य में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है) और जो कोई भी राज्य में दाखिल होता है तो समझा जाता है कि वह राज्य में अशांति फैलाने के लिए घुस रहा है।' यह केवल सम्प्रदायों के बीच की समस्या नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि इसे क्षेत्र में रोका नहीं गया तो इससे इस प्रकार का संकेत पहुंचने लगेगा जैसा कि 1990 में घाटी में हुआ था, जो आज भी हमारे गले में शर्म का हार बन कर लटका हुआ है। क्योंकि ऐसा होगा ही, जब ऐसी व्यवस्था कायम कर देंगे कि किसी को भी राज्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पता ही न चले।

कल, मेरे साथ जो कुछ हुआ, उसे मैं एकदम गौण मानता हूं। परन्तु, आपको इतना जरूर बता दूं, महोदय, इस मामले में भी, जम्मू और कश्मीर राज्य किसी एक परिवार की निजी सम्पत्ति नहीं है। यह भारत का अभिन्न अंग है। और, आपको निर्णय करना होगा कि इस पर कैसे शासन किया जाए। कोई डेढ़ वर्ष पूर्व, मैं और लोकसभा से मेरी सहयोगी श्रीमती सुषमा स्वराज वहां थीं। मैं श्री चिदम्बरम की कानूनी प्रवीणता का सम्मान करता हूं, फिर भी उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। अब, राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगाने के लिए धारा 144 का सहारा लिया गया। हम वहां किस लिए जा रहे थे? हम जम्मू में एक रैली को सम्बोधित करना चाहते थे जहां

राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना था। राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया गया। (हममें से दोनों को सशरीर उठा लिया गया और राज्य के बाहर भेज दिया। धारा 144 के अन्तर्गत वाह्य-निष्कासन का आदेश जारी किया।

कल यह सब कुछ हुआ। तब क्या होगा कि यदि कोई भाजपा शासित राज्य सरकारें किसी एआईसीसी नेताओं को अपने राज्यों में आने से रोक दें? तब क्या मीडिया, जो इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक सेंसरशिप बनाए रख रही है, वैसा ही दोहरा मानदण्ड अपनाएगी? भारत कोई कमजोर गणतंत्र नहीं है जहां आप यह कह सकते हैं कि धारा 144 लागू होगी और आप लोगों को अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे और उनके प्रवेश को रोक देंगे।

मैं आदेश पढ़ कर स्तब्ध रह गया, आदेश में प्रवेश के लिए लगाया गया प्रतिबंध निर्बाध और अनिश्चितकालीन था। इसमें तारीख तक का जिक्र नहीं था। यह है राज्य के लोकतंत्र की बदहाली। और, यह सब कुछ हो रहा है। किश्तवाड़ को भूल जाइए, आप जम्मू तक में प्रवेश नहीं कर सकते, जहां पूर्ण शांति है।

इससे पूर्व हमने क्या किया जब हम श्रीनगर और जम्मू जा रहे थे जहां तनाव बना हुआ था? आप अतिथि-गृह और सर्किट हाउस जाते, आप लोगों को बुलाते, आप लोगों के गुस्से को कम करते, आप उनकी बातें सुनते, आप सही बातें जानते। और इन सारे ब्यौरों को जानना चाहिए था।

महोदय, इस पूरी घटना की जांच की जानी चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यह घटना केवल दो समुदायों के बीच अशांति मात्र नहीं है। अन्तर्समुदाय अशांति में किसी पड़ोसी देश के झण्डों को नहीं लाया जाता है? जिन लोगों ने इस देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है और जिन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया है, उनके फोटोग्राफ तक प्रदर्शित नहीं किए गए। यह कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं है। यह भारत की सम्प्रभुता का प्रश्न है। अत:, मैं माननीय गृहमंत्री से, विशेष तौर पर वित्त मंत्री से, जो उत्तर दे रहे हैं, अनुरोध करूंगा कि वे इसे उस ढंग से न सोचें। हालांकि जो लोगो पीड़ित हुए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हम जवाबदेही के स्तर की बात भी जानना चाहेंगे कि उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जैसा कि अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति में होता है। कल की बात है कि मुझे ज्ञात सूत्रों से जानकारी मिली है कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। यह जानकर मुझे खुशी हुई है। यह गम्भीर मामला है और मैं समझता हूं कि यदि सरकार इसे हल्के से लेगी तो हमें वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो हमने 1990 में घाटी में हुई घटनाओं के लिए चुकाई थी। ■(हिंदी अनुवाद)

भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव नहीं रहे

भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिलासपुर के सांसद श्री दिलीप सिंह जूदेव का 14 अगस्त 2013 को गुडगांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। इनका जन्म 8 मार्च 1949 को हुआ था। उनके निधन के बाद राज्य सरकार ने 16 से 18 अगस्त तक राजकीय शोक रखा। श्री जूदेव का हालचाल जानने के लिए 14 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी श्री जगत प्रकाश नड्डा व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह समेत कई बड़े नेता अस्पताल पहुंचे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे श्री जूदेव ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में पर्यावण मंत्री का दायित्व भी संभाला। श्री जूदेव के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने शोक व्यक्त किया है। ■

आर.के. सिन्हा बने दिल्ली भाजपा के सह प्रभारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विधानसभा के चुनावों के प्रभारी श्री नितिन गडकरी के सहयोगी के रूप में श्री नवजोत सिंह सिद्धू के अतिरिक्त एक और सहयोगी श्री आर.के. सिन्हा की नियुक्ति की है। श्री आर.के. सिन्हा बिहार से राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य हैं।■

खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों

✍ नितिन गडकरी

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नजरिए को लेकर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भाजपा खाद्य सुरक्षा कानून के पक्ष में है। भाजपा संसद में इस संबंध में प्रस्तुत बिल का कुछ संशोधनों के साथ समर्थन भी करेगी। लेकिन हमारी चिंता इस कानून को अमल में लाने के तरीकों पर है। मुझे इससे भी एतराज नहीं है कि इस कानून को लागू कर कांग्रेस देश में अपने पक्ष में हवा बनाना चाहेगी और यह कदम 2014 या जब भी लोकसभा चुनाव होंगे, उसकी डूबती नैया को पार लगाने में मददगार साबित होगा।

हमें यह स्वीकार करने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि यह हमारी दशकों की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि देश में अनाज का विशाल भंडारण है, लाखों टन अनाज खुले आसमान में सड़ रहा है, खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि गरीबों को दो जून की रोटी भी नसीब नहीं है। यूपीए सरकार आम आदमी के नाम पर किसानों और उपभोक्ताओं के लिए केवल खोखली बयानबाजी करती है। यह सरकार कोई ऐसी ठोस खाद्य व कृषि नीति लाने में नाकाम रही है जो लोगों के हितों को सुरक्षित रख सके। इसके कारण ही किसानों को उनके उत्पादों के वाजिब दाम नहीं मिलते, जबकि उपभोक्ता कमरतोड़ महंगाई के आगे लाचार हैं।

हमें यह स्वीकार करने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि यह हमारी दशकों की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि देश में अनाज का विशाल भंडारण है, लाखों टन अनाज खुले आसमान में सड़ रहा है, खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि गरीबों को दो जून की रोटी भी नसीब नहीं है। यूपीए सरकार आम आदमी के नाम पर किसानों और उपभोक्ताओं के लिए केवल खोखली बयानबाजी करती है। यह सरकार कोई ऐसी ठोस खाद्य व कृषि नीति लाने में नाकाम रही है जो लोगों के हितों को सुरक्षित रख सके। इसके कारण ही किसानों को उनके उत्पादों के वाजिब दाम नहीं मिलते, जबकि उपभोक्ता कमरतोड़ महंगाई के आगे लाचार हैं। एनडीए बनाम यूपीए की बहस में पडने के बजाय वास्तविकता को समझना बेहतर होगा। गुजरे दस साल बदतर होते हालात का बयान करने के लिए काफी हैं।

किसी भी सरकार का यह मुख्य दायित्व है कि वह लोगों के खानपान, आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करे। इसलिए लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाले किसी भी कानून का स्वागत है। फिर भी, कुछ मुद्दों पर विचार और उनका हल निकालना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यूपीए सरकार को छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा मॉडल अपनाने में क्या परेशानी है! निष्पक्ष विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ मॉडल को सराहा है और यह पिछले कई साल से व्यावहारिक स्तर पर एकदम खरा उतरा है। इसके क्रियान्वयन में कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखा गया है। जैसे, पूर्णतया कंप्यूटरीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जीपीएस प्रणाली के जरिए इस व्यवस्था में लगे वाहनों पर निगरानी करके इसको पारदर्शी बनाया गया है। इसके साथ ही उच्च स्तर पर जवाबदेही के साथ इस प्रणाली में ग्राम पंचायतों जैसी स्थानीय इकाइयों को वरीयता दी गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपीए सरकार बेहतर शासन के सफल सिद्ध हो चुके प्रयोगों पर भरोसा नहीं करती। यह ईवीएम मशीनों यानी वोटों पर अपनी निगाह गड़ाकर जनहित योजनाओं की शुरुआत करती है। मेरा सवाल है कि क्या गरीब लोगों की भूख के साथ किसी को कोई राजनीति करनी चाहिए? अगर आप राजनीति कर रहे हों, तो आपका इरादा जनता से छुपा नहीं रहता। इस बिल से साफ है कि खाद्य सुरक्षा के नाम पर यूपीए वाहवाही लूटना चाहती है, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि देश को भूख से कैसे छुटकारा मिले?

हमें इस पहलू पर खास ध्यान देना होगा कि बिल के जरिए जिस तरीके से लाभार्थियों को लक्षित किया गया है, उससे इस सरकार का खेल उजागर हो गया है। यह शायद पहला कानून होगा जिसमें पात्रता का मापदंड तय किए बिना हरेक राज्य में लाभार्थियों की संख्या पहले से तय कर दी गई है। लाभार्थियों की पात्रता का मानदंड तय करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया गया है, इससे जाहिर है कि इसके क्रियान्वयन

में विसंगतियां पैदा होंगी। नतीजा यह होगा कि इस कानून के तहत लोगों का एक समूह अगर किसी एक राज्य में लाभ की पात्रता रखता है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी वह पात्रता रखता हो। इस प्रावधान का सीधा प्रभाव यह होगा कि गुजरात में जो 1.47 करोड़ लोग रियायती खाद्य का लाभ प्राप्त कर रहे थे, इस योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश आने के पहले गुजरात में 5.11 करोड़ व्यक्ति रियायती अनाज योजना के दायरे में आते थे, लेकिन केंद्रीय कानून बनने के बाद यह संख्या घटकर 3.66 करोड़ हो गई है। इसलिए देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बिल ने वास्तव में गुजरात में 1.47 करोड़ व्यक्तियों को रियायती अनाज लेने से वंचित कर दिया है।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उत्पादन चक्र व कृषि उत्पाद उपभोग का अंतर ही मूल्य निर्धारण की विसंगतियों की मुख्य जड़ है। साल में एक बार आने वाली फसल का साल भर उपभोग होता है। इसलिए जब तक ऐसे उत्पादों का पर्याप्त भंडारण और उनकी ढुलाई का तंत्र व्यवस्थित नहीं होगा, किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए यह हितकारी नहीं होगा। इसके लिए एक प्रभावकारी नीति की जरूरत है, जो यह सरकार नहीं कर रही।

पर्याप्त भंडारण की सुविधाएं और शीतगृहों के विकास के साथ-साथ बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग से खराब होने वाले अनाज व सब्जियों का जीवन बढ़ाया जा सकता है। अफसोस है कि सरकार के पास ऐसा ढांचा तैयार करने की कल्पना का घोर अभाव है जो लोगों के अनुकूल हो। यह एक व्यावहारिक विचार होगा कि किसानों को उचित भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बजाय इसके कि भंडारण भारतीय खाद्य निगम पर छोड़ा जाए, जिसने इस पूरी व्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है।

पर्याप्त भंडारण की सुविधाएं और शीतगृहों के विकास के साथ-साथ बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग से खराब होने वाले अनाज व सब्जियों का जीवन बढ़ाया जा सकता है। अफसोस है कि सरकार के पास ऐसा ढांचा तैयार करने की कल्पना का घोर अभाव है जो लोगों के अनुकूल हो। यह एक व्यावहारिक विचार होगा कि किसानों को उचित भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बजाय इसके कि भंडारण भारतीय खाद्य निगम पर छोड़ा जाए, जिसने इस पूरी व्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है। किसान निवेश के रूप में अपनी भूमि पर भंडारण सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए उनको सरल व आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाए, जब वह बनकर तैयार हो जाए तब सरकार उनको किराए पर ले सकती है। इसका फायदा यह होगा कि किसानों के लिए उनके गांवों में ही भंडारण की सुविधा होगी, परिवहन की लागत में कमी आएगी और अनाज को सडने से बचाया जा सकेगा।

इसी प्रकार सरकार मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इंतजार कर रही है ताकि कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की समस्या से निजात मिल सके, लेकिन इससे उन योजनाओं को धक्का लगेगा जिनमें स्थानीय सब्जी पैदा करने वाले शामिल होकर शीतगृह और उनकी शृंखला बनाकर राष्ट्रीय

संघीय संरचना पर चलने वाले देश में कानून निर्माताओं की यह जिम्मेदारी है कि कोई भी कानूनी ढांचा बनाने से पहले वे सभी विविधताओं पर विचार करें। लेकिन जब शासन पर राजनीति हावी हो जाए और जनकल्याण को सस्ती लोकप्रियता की भेंट चढ़ा दिया जाए तब गलतियां तो होंगी ही। खाद्य सुरक्षा बिल यूपीए का एक ऐसा ही हथकंडा है, जिसका खूब ढिंढोरा पीटा जाएगा ताकि वह अपनी नाकामियों पर परदा डाल सके, लेकिन लोग असलियत जानते हैं।

उत्पादन को अपने ही क्षेत्र में खराब होने से बचाते हैं। यूपीए सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित करने का भी संकेत दिया है। सरकार ऐसी नीति के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है जिससे घरेलू आवश्कताओं और निर्यात बाजार में संतुलन स्थापित किया जाए।

संघीय संरचना पर चलने वाले देश में कानून निर्माताओं की यह जिम्मेदारी है कि कोई भी कानूनी ढांचा बनाने से पहले वे सभी विविधताओं पर विचार करें। लेकिन जब शासन पर राजनीति हावी हो जाए और जनकल्याण को सस्ती लोकप्रियता की भेंट चढ़ा दिया जाए तब गलतियां तो होंगी ही। खाद्य सुरक्षा बिल यूपीए का एक ऐसा ही हथकंडा है, जिसका खूब ढिंढोरा पीटा जाएगा ताकि वह अपनी नाकामियों पर परदा डाल सके, लेकिन लोग असलियत जानते हैं। ■

(लेखक भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)
(दैनिक भास्कर से साभार)

मृत्यु शैया पर पड़े रोगी जैसी दशा

✍ यशवंत सिन्हा

वर्तमान संकट के बीज 2008-2009 में उस समय ही दिखाई पड़ गये थे, जब जाहिर तौर पर अमेरिका के वित्तीय संकट से निपटने के बहाने, भारत सरकार ने राजकोषीय विस्तार की नीति को अपनाया था। वित्तीय विस्तार ने सरकार के उपभोग व्यय को बढ़ाया और राजकोषीय घाटा जो कि 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 2.7 फीसद था, वह भी 2008-09 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 6 फीसद से अधिक का हो गया। यह काफी हद तक अनुत्पादक व्यय था, जिसने यह तथ्य उभारा कि आज राजस्व घाटे का अंश कुल वित्तीय घाटे में 40 फीसद से बढ़कर दोगुना, करीब 80 फीसद हो गया। अधिकांश उपाय सिर्फ 2009 के चुनाव में वोट जुटाने के लिए किये गये थे जिनमें किसानों की ऋण माफी, छठे वेतन आयोग, मनरेगा के आवंटन में वृद्धि आदि जैसी चीजों को शामिल किया गया था। यूपीए सरकार ने 2009 का चुनाव तो जीत लिया लेकिन उसी के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई।

सरकार में लोग इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ थे कि इस तरह का वित्तीय विस्तार मुद्रास्फीति को दबाव में ला सकता है फिर भी उन्होंने अब तक इन दबावों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने एक डॉक्टर की तरह व्यवहार किया जो अपने मरीज की बीमारी को पूरी तरह जानते हुए भी रोगियों को ऐसी दवा देता है, जिसका दुष्प्रभाव होगा। किंतु दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अभी तक हाथ बांधे हुए खड़े हैं। पिछले चार वर्षों में देश में अक्सर दोहरे अंक वाली खुदरा और अमूमन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भी मुद्रास्फीति देखी गई है। सरकार मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रही है। इसके बाद से, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्रम में अपनी मौद्रिक नीति को बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरें 2010 से 13 बार बढ़ाई हैं और साथ ही साथ तरलता को भी कम किया है। इसने निवेश पर इसका प्रभाव डाला और उससे विकास दर में भारी गिरावट आई है, जिसका सामना हम आज तक कर रहे हैं।

सरकार मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रही है। इसके बाद से, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्रम में अपनी मौद्रिक नीति को बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरें 2010 से 13 बार बढ़ाई हैं और साथ ही साथ तरलता को भी कम किया है। इसने निवेश पर इसका प्रभाव डाला और उससे विकास दर में भारी गिरावट आई है, जिसका सामना हम आज तक कर रहे हैं।

वित्तीय घाटा बढ़ने से चालू खाता घाटा (कैड) में भी वृद्धि हुई और यह बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 5 फीसद तक हो गया जबकि सन् 1991 में केवल 2.5 फीसद था। बढ़ते हुए चालू खाता घाटे को विदेश से बड़ी मात्रा में अल्पावधि उधारी तथा शेयर और ऋण बाजार में हॉट मनी की आमद से पाटने की अनुमति दी गई। एक बार फिर ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई अग्रिम कदम नहीं उठाये गए और आज जब वैश्विक परिदृश्य बदल गया है तो और हॉट मनी का यह निवेशक भारतीय बाजार से बाहर निकलने की तड़पड़ाहट में है। आज हम आर्थिक मोर्चे पर जिस बात के साक्षी हैं, वह घरेलू मुद्रास्फीति और अमेरिकी मुद्रास्फीति, के बीच बेमेल अरक्षणीय घाटे की वजह से है और अब हम इस घाटे को उन कोषों से पाटने की बात कर रहे हैं, जो भरोसे लायक नहीं है। यह हमारे अपरिवर्तनीय व्यापार में जारी असंतुलन और अब मुद्रा बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक सुगमता के सहारे समस्या को शुण्डाकार बना रहा है।

मुद्रा बाजार में अमेरिकी मात्रात्मक सुगमता कोई जादुई पत्थर नहीं थी। बाद की तुलना में इसको पहले ही पहचान लिया गया होता तो कोई बड़ी समस्या

न आती। जैसा कि अन्य क्षेत्रों में विकास की आशा को पहचाने और इसके लिए खुद को तैयार करने में भारत सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आज जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी भुगतना पड़ रहा है और अब जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार आ चुका है तो भी भारत अभी तक समस्या से ग्रस्त है। दुनिया के बाजारों, रेटिंग एजेंसियों, कॉरपोरेट्स आदि सबने भारत सरकार की ओर से कार्रवाई के कुछ संकेत देखे थे, लेकिन सरकार की नीतियों में पक्षाघात केवल बढ़ता ही गया। तरलता दबाव और ब्याज दरों में वृद्धि ने केवल पैसे को असहनीय ही नहीं बल्कि अनुपलब्ध भी बनाया है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और अन्य प्रशासनिक कारणों की वजह से या तो परियोजनाओं में देरी हुई या फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सरकार ने सिर्फ कामकाज बंद कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू और विदेशी निवेशकों में अविश्वास फैल गया और आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट गया जिसकी वजह से हम एक दैनिक आधार पर शेयर बाजार का नरसंहार और रुपये का वध देख रहे हैं।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक बीमारी के बजाय इसे लक्षण मानते हैं और उन्होंने जो कुछ कदम उठाये हैं वे अक्सर उलटे साबित होते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण खो दिया है। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि अगर मैं इस स्थिति में होता तो क्या करता? मैं कहना चाहूंगा कि यह एक अनुचित सवाल है। आप एक डॉक्टर द्वारा गलत निदान और उपचार के बाद लाये गये उस रोगी को नहीं ले सकते जो कि अपनी मृत्युशय्या पर पड़ा हो और जिसके बाद डॉक्टर आपसे उसे बचाने की गुहार कर रहा हो। शायद, रोगी को अब भी बचाया जा सकता हो लेकिन इसके पहले पुराने चिकित्सक से छुटकारा मिलना आवश्यक होगा। रोगी को बेहतर सुविधाओं और डॉक्टरों युक्त किसी अन्य अस्पताल में भेजा जा सकता है, जहां चिकित्सकों का एक नया समूह दिल में प्रार्थना और विश्वास के साथ उसका इलाज शुरू करेगा।

1998 में मैं जब वाजपेयी सरकार में देश का वित्त मंत्री बन गया था, तब पूर्वी एशियाई संकट अपने चरम पर था। रुपया डॉलर के मुकाबले मूल्य खो चुका था और हम विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर अपना खून बहा रहे थे। भावनाओं की तो पूछिए ही मत लेकिन अगस्त, 1998 में एक झटके के साथ में रिसर्जेंट इंडिया बांड जारी करने के माध्यम से हमने अपनी धारणा बदली और आत्मविश्वास से भर गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि यही आज एक मात्र समाधान है पर इसी तरह का जज्बा करने की आज भी जरूरत है। दुर्भाग्य से इस सरकार को वह फायदा नहीं है, जो हमें 1998 में था। हम सत्ता में नये थे और कुछ भी करने में समर्थ थे। यह सरकार अब पैरालिसिस से ग्रस्त है और अपने दिन गिन रही है। इनके पास सिर्फ एक रास्ता यह है कि यह अपना काम समेटे और जल्द से जल्द सत्ता छोड़ दे। देश में फिर से चुनाव होने चाहिए और नई सरकार का आह्वान किया जाना चाहिए। शायद चुनाव की घोषणा ही बाजार में स्थिरता ला सके, जो कि सरकार अभी तक अपनी किसी भी नीति से नहीं ला पाई है। ■

(लेखक भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री हैं)

(साभार : राष्ट्रीय सहारा)

यह सरकार अब पैरालिसिस से ग्रस्त है और अपने दिन गिन रही है। इनके पास सिर्फ एक रास्ता यह है कि यह अपना काम समेटे और जल्द से जल्द सत्ता छोड़ दे। देश में फिर से चुनाव होने चाहिए और नई सरकार का आह्वान किया जाना चाहिए। शायद चुनाव की घोषणा ही बाजार में स्थिरता ला सके, जो कि सरकार अभी तक अपनी किसी भी नीति से नहीं ला पाई है।

भाजपा प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 17 अगस्त, 2013 को निम्नलिखित चार प्रदेशों के प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है:-

1. त्रिपुरा के प्रभारी श्री विजय जौली होंगे।
2. सिक्किम के प्रभारी श्री दिनेशानंद गोस्वामी होंगे।
3. दादरा नगर हवेली की प्रभारी श्रीमती पूनम महाजन होंगी और
4. दमन एवं द्वीव के प्रभारी श्री किरीट सोमैय्या होंगे।

इसके अतिरिक्त श्री राजनाथ सिंह ने केन्द्रीय कार्यालय के सचिव पद पर श्री अरुण जैन की नियुक्ति की है।

कांग्रेस को नहीं दिखती जिहादी साजिश

✍ बलबीर पुंज

कांग्रेस पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जवाबदेह ठहराने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि 2014 के चुनावों में अल्पसंख्यक वोट बैंक की उसकी एकमात्र उम्मीद बची है।

किश्तवाड़ में 9-12 अगस्त को हुई हिंसक घटनाओं पर बयान देते हुए, केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने वही गलती क्यों दोहराई जो गलती उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी एवं रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने 6 अगस्त को नियंत्रण रेखा पर हुई घटना पर दिये गये अपे पहले बयान में की थी? श्री एंटोनी ने 6 अगस्त को सीमा पर हुई गोलीबारी और भारतीय सैनिकों की हत्या में पाकिस्तान सेना का हाथ होने की बात नकारने का प्रयास किया था। देश में भड़के आक्रोश एवं सेना प्रमुख के निष्कर्ष ने उन्हें अपना बयान बदलने एवं इस्लामाबाद की संलिप्तता मानने पर मजबूर किया। इस बीच पाकिस्तान को कूटनीतिक लाभ मिल गया था और हमारी सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बचाव करने के सोचे समझे प्रयास के कारण उपहास का पात्र बनी। यदि पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को अपनी सेना से डरना पड़ता है, क्योंकि वहां पर सेना द्वारा निर्वाचित सरकारों का तख्ता पलट दिये जाने का इतिहास रहा है, तो यह वो जाने।

> ***विडंबना यह थी कि जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन गृहमंत्री सज्जाद अहमद किचलू उस दिन किश्तवाड़ में मौजूद थे, चूंकि कस्बा उनके चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। अत: उनकी भूमिका स्वाभाविक रूप से राष्ट्रविरोधी थी कि श्री अब्दुल्ला को उनसे इस्तीफा लेने पर बाध्य होना पड़ा। यदि सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस स्वयं के नेताओं को जिहादियों के साथ शामिल पाती है, तो मुख्यमंत्री अब्दुल्ला देश को क्या मुंह दिखायेंगे?***

यदि पाकिस्तान की सरकार जिहादी समूहों के जबर्दस्त दबाव में है, तो यह पुन: एक मुस्लिम देश के विचार पर आधारित विभाजन के दोषपूर्ण तर्क को जाहिर करता है। आज, सुन्नियों और शियाओं की रोज हत्याएं होना, जो एक-दूसरे की मस्जिदों को बम का निशाना बनाते हैं, न केवल पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान, नाइजीरिया और माली में भी ऐसा होता रहता है, और इस्लामी सम्प्रदायों की परस्पर असहिष्णुता अधिकतर मुसलमान बहुल देशों में, उम्मा की असलियत को जाहिर करती है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो वह एक ऐसी इमारत पर खड़ा है जिसकी तीन अस्थिर टांगें हैं- सेना, मुल्ला और निर्वाचित सरकार और ये तीनों परस्पर सांठगांठ के साथ-साथ एक-दूसरे को काटते हैं।

इस महीने पूर्व में, जमात-उद-दावा का नेता हाफिज सईद, जो 26/11 के मुंबई हमलों का प्रमुख संदिग्ध सूत्रधार है, ने लाहौर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान भारत के खिलाफ अपनी धमकी दोहराई। नवाज शरीफ की निर्वाचित सरकार ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

अब, श्री चिदंबरम जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सुर में सुर मिलाकर इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि किश्तवाड़ में हिन्दुओं और सिखों को निशाना बनाकर किये गये हमले मात्र साम्प्रदायिक दंगों के परिलक्षण हैं जिहादी लड़ाई का विस्तार नहीं जो पाकिस्तान में रहने वाले तत्वों द्वारा राज्य के गैर मुसलमान निवासियों के खिलाफ छेड़ी गई है? जिस तरह से स्थितियां उत्पन्न हुई हैं- और भीड़ द्वारा भारत विरोधी नारे लगाये जा रहे थे, ईद की नमाज के बाद पाकिस्तानी झंडे लहराये जा रहे थे, मगर सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत बयान में इन बातों की अनदेखी की गई है। यह भी कि बकि हिन्दू और सिखों के व्यावसायिक स्थानों पर किश्तवाड़ में हमले किये जा रहे थे, ऐसे ही हमले जम्मू-क्षेत्र में 14 अन्य स्थानों पर साथ ही साथ किये जा रहे थे। आधिकारिक बयान में उन्हें भी अनदेखा कर दिया गया। सरकार सरल से सवाल का जवाब देने में असमर्थ है: जबकि सेना किश्तवाड़ में मौजूद थी फिर भी स्थिति पर काबू करने के लिये उसे तुरंत क्यों नहीं बुलाया गया?

विडंबना यह थी कि जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन गृहमंत्री सज्जाद अहमद किचलू उस दिन किश्तवाड़ में मौजूद थे, चूंकि कस्बा उनके चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। अत: उनकी भूमिका स्वाभाविक रूप से राष्ट्रविरोधी थी कि

श्री अब्दुल्ला को उनसे इस्तीफा लेने पर बाध्य होना पड़ा। यदि सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस स्वयं के नेताओं को जिहादियों के साथ शामिल पाती है, तो मुख्यमंत्री अब्दुल्ला देश को क्या मुंह दिखायेंगे?

श्री अब्दुल्ला भारतीय राजनीतिक दलों, खासकर भाजपा पर पाकिस्तानी जिहादियों व उनके स्थानीय सहयोगियों व उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा चिनाब घाटी में नस्ली सफाया किये जाने को लेकर आगाह करने के चलते, आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा: 'भाजपा का उद्देश्य 2008 की स्थितियों को पुन: पैदा करने पर आधारित लगता है, जब अमरनाथ भूमि को लेकर प्रदर्शन हुए थे, जिससे कि वे संसद और विधानसभा चुनावों में उसका लाभ उठा सकें।'

लेकिन श्री अब्दुल्ला सच्चाई से क्यों भयभीत हैं? उनके पास इस बात का क्या स्पष्टीकरण है कि उन्होंने किश्तवाड़ में हिंसा पर काबू करने के लिए छह घंटे बाद तक सेना को क्यों नहीं बुलाया? यह कि मुख्यमंत्री सच बताने से कबतरा रहे हैं यह बात उनके द्वारा राज्य में समाचार चैनलों को बंद किये जाने के निर्णय से जाहिर होती है। किश्तवाड़ में जिहादी से जाहिर होती है। किश्तवाड़ में जिहादी तत्वों की एक पवित्र अवसर को भारत विरोधी प्रदर्शन में रूपांतरित करने की क्षमता और क्षेत्र से हिन्दुओं और सिखों को खदेड़ने के लिए अभियान चलाना, नेशनल कांफ्रेंस नीत सरकार द्वारा मुस्लिम बाहुल्य वाले राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने योग्य है। इस आरोप में केन्द्र सरकार को भी साझीदार होना पड़ेगा।

पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने एवं उनके साथ शांति प्रक्रिया की आगे बढ़ाने की जल्दबाजी में जबकि पाकिस्तान में शक्तिशाली तत्व काबुल में तालिबानी शासन को पुनर्स्थापित करने और तालिबानी लड़ाकों को भारत, खासकर कश्मीर की तरफ मोड़ने के इरादे से अगले साल अफगानिस्तान से होने वाली अमेरिकी सेनाओं की वापसी का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं- नयी दिल्ली भारत के व्यापक सुरक्षा हितों की अनदेखी कर रही है।

सत्ताधारी कांग्रेस के लिए 2014 में होने वाले चुनावों का हौआ बनता जा रहा है। जबकि प्रत्येक चुनावी सर्वेक्षण कांग्रेस के कानों में घंटी बजा रहा है, पार्टी हताशा की स्थिति में है। पतन की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था के संकेत यह बता रहे हैं कि कांग्रेस बुरी हालत में है। जब प्याज के दाम 80 रुपए प्रति किलो और टमाटर 130 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, यह बताने के लिए महंगाई सूचकांक की जरूरत नहीं कि जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।

औद्योगिक उत्पादन गिर गया है, रुपया प्रतिदिन लुढ़क रहा है, उपभोक्ता खर्च नहीं कर रहे क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, सेवा क्षेत्र में रोजगार घट रहे हैं और व्यापारों से कर्ज चुकता न हो पाने के चलते राज्य स्वामित्व के बैंकों की भी स्थिरता खतरे में है। अत: कांग्रेस के पास अब केवल एक नारा बचा है और वह है कि पंथनिरपेक्षता को खतरा। ऐसी चुनावी रणनीति उसे अपने मुसलमान वोट बैंक को अधिक सुदृढ़ बनाने में मददगार होगी।

और यही करण है कि कांग्रेसनीत सरकार यह घोषित नहीं करना चाहती कि पाकिस्तान प्रयोजित जिहाद भारत का नंबर एक दुश्मन है और देश में भारत विरोधी सहयोगियों की मौजूदगी है। यह आश्चर्यजनक है कि लाहौर में ईद पर हाफिज सईद के भाषण के बाद, सरकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कहने और उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का आह्वान पाकिस्तान की धरती से किये जाने की छूट देने का जिम्मेदार ठहराने में विफल रही।

ईद के मौके पर किश्तवाड़ में अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद जम्मू क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के हमले हुए। जिस तरह की तीव्रता और सुस्पष्टता इन हमलों में थी, वह नस्ली सफाये के इरादों को परिलक्षित करती है। 90 के दशक की घटनाएं, जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया गया था, उसमें भी ऐसी ही पद्धति अपनाई गई थी और अब इतिहास दोहराया जा रहा है।

यदि राजनीतिक दलों को अपनी आंखों के सामने इस साजिश का खुलासा होता नहीं दिख रहा, तो वे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से गैर मुसलमानों का सफाया करने और इस तरह शेष भारत से राज्य के रिश्तों को कमजोर बनाने की जिहादी योजना का समर्थन कर रहे हैं।

यदि राजनीतिक दलों को अपनी आंखों के सामने इस साजिश का खुलासा होता नहीं दिख रहा, तो वे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से गैर मुसलमानों का सफाया करने और इस तरह शेष भारत से राज्य के रिश्तों को कमजोर बनाने की जिहादी योजना का समर्थन कर रहे हैं। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

पॉयोनियर से साभार

भाजपा का लोकसभा में 272+ तथा विधान सभा चुनावों में जीतने का संकल्प

गत 18 अगस्त 2003 को आगामी पांचवी विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों की तैयारी के बारे में राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और महत्वपूर्ण नेताओं की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। यहां हम भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह तथा भाजपा चुनाव अभियान समिति तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों के प्रमुख बिन्दु प्रस्तुत कर रहे हैं:

बैठक का उद्घाटन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनावों के लिए ''मिशन 272+'' और चार विधान सभा चुनावों में विजय प्राप्त करने का आह्वान किया।

श्री राजनाथ सिंह ने अर्थव्यवस्था की बदइंतजामी के लिए प्रधानमंत्री की भर्त्सना करते हुए कहा कि इसमें आम आदमी की कठिनाईयां और पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। मुद्रास्फीति के कारण परिवार का बजट तबाह होता जा रहा है जिसे और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। रुपए का लगातार हो रहा मूल्यह्रास सरकार की जबरदस्त विफलता का प्रतीक है जिससे यही पता चलता है कि सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सभी दायरों का प्रबंध कर पाने में असफल है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया भाषण प्रेरणारहित था और इससे घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास और भी भंग हुआ है। पूंजी नियंत्रण शुरू करने का निर्णय पीछे गिरने वाली पद्धति है और इससे अर्थव्यवस्था को और झटका लगेगा।

श्री राजनाथ सिंह ने सरकार से मांग की कि वह पाकिस्तान के साथ तब तक किसी भी प्रकार का संवाद न करे जब तक वह अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करने का भरोसेमंद वचन न दे और साथ ही यह भी वचन दे कि सीमा पर झड़पें बंद की जाएंगी। श्री राजनाथ सिंह के अनुसार पिछले 10 दिनों में सीमा पर 18 बार उल्लंघन, भारतीय पेट्रोल दस्तों पर घात लगाकर हमला, किश्तवाड़ में अलगाववादियों को उकसाने और बढ़ती जा रही घुसपैठियों को बचाने की पृष्ठभूमि में नितांत आवश्यक है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस तो बस अपनी रक्षा करना चाहती है और उसे देश की आर्थिक, आतंरिक तथा बाह्य सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं रह गया है।

चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष तथा गुजरात के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमें प्रभावकारी प्रचार करना और हर वोटर तक पहुंचना एक दम आवश्यक है। उन्होंने इस बात का भरोसा जताया कि भाजपा जबदरस्त विजय हासिल करेगी क्योंकि देश के लोग कांग्रेस के कुशासन से बुरी तरह त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि लोग पहले उपलब्ध अवसर पर ही कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि जोरदार विजय हासिल करने के लिए विस्तार से योजना तैयार करना और इसे पूरी तरह से क्रियान्वित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता और संगठन भाजपा की मूल जड़ है। हमें इस बात का पूरा प्रयास करना होगा कि हम अगले 200 दिनों में समाज के सभी वर्गों को पार्टी में लाएं और संगठन को मजबूत करें। उन्होंने अपील की कि सभी नियुक्त समितियों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच कर और भी तेजी से काम करना आवश्यक है।

भाजपा बैठक में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुरन्त उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। सामूहिक रैलियां, निर्वाचन-क्षेत्र स्तर के सम्मेलन, एक-एक व्यक्ति के घर तक पहुंचने के लिए अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया गया। श्री लालकृष्ण आडवाणी ने समापन सत्र मे अपने परामर्श से मार्गदर्शन किया। ■

हर मोर्चे पर विफल सरकार

✍ ए. सूर्यप्रकाश

यह स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग मूड-माहौल में मनाया गया। आज एक ऐसा माहौल है जिसमें आत्ममंथन की अधिक जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति, संप्रग सरकार की देश को सही ढंग से चलाने की अक्षमता, भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले, अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत, रुपये में अभूतपूर्व गिरावट, धरना-प्रदर्शन और देश के अनेक भागों में बढ़ती हिंसा, नए राज्यों के गठन की मांग में उछाल, संसद की पंगुता और राजनीतिक तबकों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखने जैसी समस्याएं देश के सामने मुंह बाए खड़ी हैं।

आज से पहले देश कभी इतनी सारी समस्याओं से एक साथ नहीं जूझा। सीमा पर गतिविधियां इसलिए चिंता का विषय नहीं बनीं क्योंकि चीन फिर से दबंगई दिखा रहा है, बल्कि इस मसले पर सरकार की भीरुता के कारण यह स्थिति विकसित हुई है। भारतीयों को यह जानकर झटका लगा कि केंद्र सरकार ने पहले तो इस तथ्य को छिपाने का प्रयास किया कि चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है और बाद में अफरातफरी में समझौते का बहाना बनाकर देश को मूर्ख बनाने का प्रयास किया। दरअसल, इस समझौते के तहत भारत अपने भूभाग से अपनी सेना को हटाने के लिए मजबूर हुआ है। चीन के प्रति हमारी घुटना टेकू नीति से उत्साहित होकर पाकिस्तान भी भारत को आंखें दिखाने लगा। पाकिस्तानी सेना द्वारा पांच भारतीय सैनिकों की हत्या की हालिया घटना इस बात का उदाहरण है कि पाकिस्तान भारत को कितने हलके में ले रहा है और इसका श्रेय वर्तमान सरकार के मुखिया में संकल्प के अभाव को जाता है। पर देश के लोगों को जिस बात ने सबसे अधिक हताश किया वह केंद्र सरकार के प्रमुख नेताओं के बयान थे कि यह घटना शांति प्रक्रिया और अगले माह भारतीय व पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों की बैठक में कोई बाधा नहीं बनेगी।

इन घटनाओं से पता चलता है कि संप्रग सरकार में भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का ही माद्दा नहीं है और यह पाकिस्तान व चीन के साथ शांति प्रक्रिया जारी रखकर देश के सशस्त्र बलों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है। इसमें संदेह नहीं कि संप्रग सरकार को अपनी लचर नीतियों का खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, किंतु बहुत से भारतीय इस चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं कि कहीं मनमोहन सरकार इतना नुकसान न कर बैठे कि भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति संभव न रहे।

मूड बिगाड़ने वाला एक और पहलू है भ्रष्टाचार का राक्षस और इसके खात्मे की सरकार की अनिच्छा। राष्ट्रमंडल खेल, 2जी स्पेक्ट्रम, कोलगेट घोटाला आदि ने संप्रग सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व के दामन पर दाग लगा दिया है। सीएजी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा इन घोटालों की जांच-पड़ताल से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों के सूत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जुड़े हुए थे। खदान और 2जी स्पेक्ट्रम पर संदेहास्पद फैसलों की आंच प्रधानमंत्री तक भी पहुंची है। दस साल पहले उनकी मिस्टर क्लीन की जो छवि थी, वह दागदार हो चुकी है। मनमोहन सिंह ने सोनिया और राजीव गांधी के मित्र ओत्तोवियो क्वात्रोची को बोफोर्स तोप में घूस के तौर पर मिले 73 लाख डॉलर के साथ निकल जाने का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमें सीएजी की हालिया रिपोर्ट मिली जिसमें वीआइपी हेलीकॉप्टर में घोटाले का खुलासा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को दूसरे घोटाले का

संप्रग सरकार में भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का ही माद्दा नहीं है और यह पाकिस्तान व चीन के साथ शांति प्रक्रिया जारी रखकर देश के सशस्त्र बलों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है। इसमें संदेह नहीं कि संप्रग सरकार को अपनी लचर नीतियों का खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, किंतु बहुत से भारतीय इस चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं कि कहीं मनमोहन सरकार इतना नुकसान न कर बैठे कि भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति संभव न रहे।

खुलासा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे को लेकर हुआ। उन्होंने कुछ ही वर्षो में जमीन के सौदों में सैंकड़ों करोड़ की संपत्ति बना ली है। इन घोटालों ने मनमोहन सिंह की स्वच्छ छवि को दागदार कर दिया है। रही सही कसर देश की अर्थव्यस्था की खस्ता हालत ने पूरी कर दी है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वह बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनकी आर्थिक नीतियों का यह हश्र क्यों हुआ? रुपये में गिरावट, बढ़ता बजट घाटा, आसमान छूती महंगाई, अर्थव्यवस्था का खराब प्रदर्शन खासतौर पर विनिर्माण क्षेत्र में घटती विकास दर ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रख दी है। इसने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की मनमोहन सिंह और पी. चिदंबरम की क्षमताओं पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं।

आखिर में, कुछ शब्द राजनीतिक बिरादरी पर। हमारी संसद और बहुत से राज्यों की विधानसभाओं में काम नहीं हो पा रहा है। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। परिणामस्वरूप पूरा विधायी तंत्र पंगु हो गया है। राजनीतिक सुधारों पर अदालतों और केंद्रीय सूचना आयोग के फैसलों के विरोध में पूरी संसद एकजुट हो गई है। दो साल या इससे अधिक की सजा पाए व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया था, चाहे उन्होंने उच्च अदालतों में अपील क्यों न दायर कर रखी हो। यह चुनाव सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का बेहद महत्वपूर्ण फैसला है, जिसके खिलाफ तमाम दलों के राजनेता जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन के लिए एकजुट हो गए हैं। उन्होंने एक बार फिर न्यायपालिक पर हमला शुरू कर दिया है। इस सबसे आम नागरिक निराश-हताश है। उन्हें लग रहा है कि लोकतंत्र विफल हो रहा है। अब यहां से हम कहां जाएंगे?■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

(दैनिक जागरण से साभार)

सात संभागों की एक सी कहानी, सब जगह लोग भ्रष्टाचार से परेशान : वसुन्धरा राजे

– संवाददाता द्वारा

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि 4 अप्रैल से शुरू हुई उनकी सुराज संकल्प यात्रा का पड़ाव बांदीकुई में खत्म हुआ है। चारभुजा से लेकर बांदीकुई तक के साढ़े 14 हजार किलोमीटर लम्बे इस सफर में वे जहां भी गई हालात एक जैसे। सब जगह लोग भ्रष्टाचार से परेशान। पूरे राजस्थान में सरकार कहीं नहीं। सब जगह हाहाकार। न बिजली, न पानी, न सड़क, न कानून व्यवस्था, न रोजगार, न महिलाओं को सम्मान, न किसानों को वाजिब दाम, जिधर देखो उधर लूट का आलम। आंख बंद कर लो तो सात के सात संभागों की एक सी कहानी। श्रीमती राजे 11 अगस्त को अलवर जिले के राजगढ़ और दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे में विशाल जनसभाओं को सम्बोधित कर रही थी।

भ्रष्टाचार से खजाना खाली

श्रीमती राजे ने कहा कि कांग्रेस ने भांप लिया कि अब वह सत्ता में दोबारा आने वाली नहीं है। इसलिये दोनों हाथों से सरकार अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। भ्रष्टाचार कर-कर के इस सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया है और अब जब चुनाव आ गये तो उसी पैसे में से मामूली राशि बांटकर जनता को लुभाना चाहती है। जनता अब लालच में आने वाली नहीं है।

पांच साल की कार्य योजना के साथ देंगे नई सरकार

श्रीमती राजे ने कहा कि इस सरकार के पास न तो कोई विकास का रोड मैप है और न ही कोई वीजन। हम पूरे पांच साल की कार्य योजना बनाकर राजस्थान को एक मजबूत और नई सरकार देंगे, जिसका एजेण्डा सिर्फ और सिर्फ विकसित और नया राजस्थान होगा। क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान में 53 साल सरकार देकर अब तक उसे पिछड़ेपन के गड्ढे में ही रखा।

पैसा बनाने में लगे रहे मुख्यमंत्री

राजे ने कहा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक पूरे पांच साल पैसा बनाने में लगे रहे। कभी जमीनों के नाम पर तो कभी होटलों के नाम पर। कभी नौकरियों के नाम पर, तो कभी खानों के नाम पर मुख्यमंत्री अपनी जेबें भरते रहे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी जमीनों का कारोबार करवा दिया।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव भूपेन्द्र यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉ. दिगम्बर सिंह, नाथूसिंह गुर्जर, विरेन्द्र मीणा, शैलेन्द्र जोशी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक रोहिताश्व शर्मा, हेमसिंह भडाना, ज्ञानदेव आहूजा, डॉ. जसवंत यादव, बनवारी लाल सिंघल, बहादुर कोली, पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा, अलवर जिलाध्यक्ष संजय शर्मा, दौसा जिलाध्यक्ष डॉ. रतन तिवाड़ी आदि उपस्थित थे। ■

देश बेचैन है कांग्रेस के कुशासन से मुक्त होने को : नड्डा

श्री जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्में श्री नड्डा को अपनी युवावस्था में जेपी आंदोलन ने प्रेरित किया था और वे पहले छात्र युवा संघर्ष समिति के सचिव के रूप में शामिल हुए तथा बाद में उन्होंने 1977-79 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पटना विश्वविद्यालय में भाग लिया। युवा नेता के रूप में उन्होंने एबीवीपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी में सफलतापूर्वक अनेक उत्तरदायी पदों पर काम किया। 1991-94 के बीच भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लगातार युवा-सम्बन्धी मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई तथा कांग्रेस सरकार द्वारा देश में कमजोर करने के प्रयासों का सदैव विरोध करते रहे। उन्होंने अपने पूरे राजनैतिक जीवन में अथक संघर्ष करते हुए लोकतांत्रिक साधन अपनाकर आज की शासन-पद्धति की विफलताओं को उजागर किया। श्री नड्डा को स्कूलों के अप-ग्रेड करने के संघर्ष के दौरान 45 दिनों तक हिरासत में रखा गया था।

श्री नड्डा हिमाचल विधानसभा के लिए कई बार निर्वाचित हुए और उन्होंने राज्य के अनेक मंत्रीपदों की जिम्मेदारियां संभालते हुए अपनी क्षमता और योग्यता का प्रमाण दिया। वे 2010 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने और 2012 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में वे आगामी विधान सभा चुनावों में पार्टी को तीसरी बार जिताने में अपना पूरा राजनैतिक अनुभव लगा रहे हैं।

कमल संदेश के सम्पादक मण्डल के सदस्य **श्री राम प्रसाद त्रिपाठी** *ने श्री नड्डा के साथ एक विशेष साक्षात्कार किया, जिसमें उन्होंने वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति पर चर्चा करते हुए अपना यह मत बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रगट किया कि आज देश के लोग कांग्रेस कुशासन से मुक्त होने के लिए व्यग्र हैं। उन्होंने भाजपा की योजनाओं तथा उसकी तैयारियों की बात भी की ताकि कांग्रेस-नीत यूपीए को केन्द्र की सत्ता से उखाड़ फेंका जा सके और भारत को फिर से विकास के मार्ग पर लाया जा सके। साक्षात्कार के प्रमुख अंश प्रस्तुत हैं:*

प्र.: डा. रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने निरंतर ही छत्तीसगढ़ में अच्छा कार्य कर दिखाया है। राज्य में भाजपा के प्रभारी के रूप में, क्या आप समझते हैं कि भाजपा आगामी चुनावों में इस विगत परफोर्मेंस को देखते हुए फिर से विजय प्राप्त कर 'हैट्रिक' लगाएगी?

- विकास तथा जन कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में रमन सिंह सरकार के रिकार्ड को राज्य के लोगों ने जबरदस्त प्रशंसा की है जैसा कि पार्टी की चुनावी सफलताओं से प्रगट होता है। भाजपा सरकार की विश्वसनीयता ने छत्तीसगढ़ में विजयी वातावरण बना दिया है, अत: इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि आगामी चुनावों में निश्चय ही भाजपा 'हैट्रिक' विजय प्राप्त करेगी।

प्र.: बस्तर में नक्सल हमले की एनआईए रिपोर्ट से पता चलता है कि मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार कुछ कांग्रेसी भी इस भयावह हमले में शामिल थे। राज्य के कांग्रेसी नेताओं पर नक्सली हमले के परिणामस्वरूप कांग्रेसियों ने सत्तारूढ़ भाजपा पर राजनीतिक प्रश्न उठाने की कोशिश की है। कांग्रेस के इस घृणित योजना का पर्दाफाश करने के लिए भाजपा लोगों को कैसे समझाएगी?

- भाजपा सरकार ने नक्सल मुद्दे को बड़ी दृढ़ता और बिना किसी पूर्वाग्रह के संभाला है। मुख्यमंत्री ने सदैव ही इस मुद्दे का समाधान मानवीय दृष्टिकोण से किया है। इसी कारण कांग्रेसी नेता भी डा. रमन के फैसलों पर अपना

विश्वास व्यक्त करते हैं। जो कुछ बस्तर में हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था, किन्तु मीडिया में छपी एनआईए रिपोर्ट ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट से कई प्रकार के प्रश्न उभरे हैं, जैसे किसने यात्रा का मार्ग बदला और बिल्कुल अन्तिम क्षण में किसकी अनुमति से रैली स्थल में परिवर्तन किया गया? किसने नक्सलवादियों को यात्रा के मार्ग का पता दिया और वे कौन से प्रमुख नेता थे, जो बस्तर में जुलूस पर हमले से पहले गायब हो गए? लोगों को इनका उत्तर मालूम है और वे समुचित समय पर जवाब देंगे।

प्र.: भाजपा प्याज की कीमतों के बढ़ने पर 1998 में तीन राज्यों में हारी। अब 2013 में, प्याज की कीमतों ने पुराने सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं। क्या आप समझते हैं कि आगामी चुनावों में प्याज की कीमत मुद्दा होगा?

– यह तो मात्र एक मुद्दा है, परन्तु सामान्य रूप से, महंगाई, रुपए की गिरावट, औद्योगिक उत्पादन में कमी, किसान एवं कृषि की हालत, बेरोजगारी की चुनौती और यूपीए द्वारा अर्थव्यवस्था की बदइंतजामी भी उतने ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भाजपा निश्चय ही इन सभी मुद्दों को जनता की अदालत में ले जाएगी। 1998 में, प्याज की कीमतों में वृद्धि केवल एक ही मुद्दा था परन्तु 2013 में तो देश के सामने मुद्दों की भरमार है जिनका जवाब यूपीए सरकार को देना होगा।

प्र.: कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार का कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार और अकुशलता ने देश के विकास को पटरी से उतार दिया है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस सदा ही इन मुद्दों से बचना चाहती है। क्या आप समझते हैं कि भाजपा यूपीए सरकार की इन काली करतूतों का पर्दाफाश कर पाएगी?

– भाजपा ने निरन्तर कांग्रेस की जन-विरोधी नीतियों का विरोध किया है और लोगों के सामने कांग्रेस सरकार की असली चेहरा लाने की हर संभव कोशिश की है। हम तब तक निरन्तर ऐसा करते रहेंगे जब तक लोग कांग्रेस को केन्द्र में सत्ता से बाहर न कर दें। सीडब्ल्यूजी, 2जी, आदर्श, एंट्रिक्स घोटाला, कोल-गेट, रेल-गेट, संदिग्ध रक्षा सौदे और कोल-गेट फाइलों का गायब होना जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भाजपा ने संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त संघर्ष किया है। हमने जेपीसी में सरकार के हाथ बांध दिए थे और उसे कोर्ट की निगरानी में जांच कार्य करने पर विवश कर दिया था। किन्तु, यूपीए है कि वह किसी भी तरह से अपराधियों की रक्षा करने पर तुली हुई है। भाजपा तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक ये अपराधी सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं।

प्र.: आज देश का युवा वर्ग महंगाई, भारी भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से परेशान है। भाजपा युवा सम्बन्धी इन मुद्दों का समाधान कैसे करेगी?

– गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकारों ने युवाओं के हित में अनेक कदम उठाए हैं। यदि इन सरकारों की लोकप्रियता आपको कोई संकेत देती है तो स्पष्ट है कि भाजपा सरकारों ने शानदार प्रशासन दिया है, जिसकी युवा वर्ग सराहना करता है। आज युवाओं की अदम्य इच्छा है कि उन्हें सुशासन, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन और परफोर्मेंस मिले और हमने इन सभी मोर्चों पर अच्छा काम कर दिखाया है और आगे भी ऐसा ही करने का प्रयास जारी रहेगा।

प्र.: आप भाजपा के युवा-नेतृत्व के प्रतिनिधि हैं। क्या आप समझते हैं कि भाजपा ने पार्टी के युवा-नेताओं को तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं?

– यदि आप भाजपा के राज्य और राष्ट्रीय संगठनों के गठन को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भाजपा ने युवा नेताओं को पर्याप्त अवसर और प्रमुख स्थान प्रदान किए हैं। यदि हम अन्य राजनैतिक दलों से तुलना करें तो आज भाजपा सबसे अधिक युवा पार्टी है। हम अभी हाल में पार्टी में विभिन्न पदों पर नया खून लाने के प्रयास को जारी रखेंगे।

प्र.: भाजपा ने सोशल मीडिया पर अच्छा खासा जोर दिया है। क्या सोशल मीडिया हमारे कार्यकर्ताओं की जमीनी और बूथ स्तरीय कार्य का स्थान ले पाएगी या आप क्या समझते है। कि पार्टी इन दोनों के बीच संतुलन कायम करेगी?

– इन दोनों का अपना महत्व है और किसी को भी दूसरे की कीमत पर लादा नहीं जा सकता है। हम आगामी चुनावों में दोनों पारस्परिक मोबिलाईजेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से मोबिलाईजेशन को बराबर का महत्त्व देंगे।

प्र.: भाजपा को शहरी मध्य-वर्ग की पार्टी समझा जाता है और चुनावी पण्डित मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में

इसकी उपस्थिति अधिक नहीं है। इस बार भाजपा ग्रामीण मतदाताओं को कैसे रिझा पाएगी?

– मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि भाजपा शहरी मध्यवर्ग की पार्टी है। भाजपा लोगों की पार्टी है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिसा और कर्नाटक जैसे विभिन्न राज्यों में विगत में सत्तारूढ़ हो चुके हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब हमने शहरों और गांवों दोनों में जड़ें जमा ली हों। हमारे अधिकांश नेता भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि भाजपा को शहरी पार्टी का नाम देना बिल्कुल उचित नहीं है।

प्र.: 2009 लोकसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस ने फर्म ऋण माफी योजना जैसी लोकप्रिय योजनाएं लाई थी और इस बार भी वह उसी नीति का अनुसरण कर रही है। अब फिर से वह फूड सिक्योरिटी बिल, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और लैंड एक्वीजीशन बिल आदि लाने की योजना बना रही है। भाजपा कांग्रेस की इन मुफ्त के माल देने और लोकप्रिय योजनाओं का सामना किस प्रकार करेगी?

– कांग्रेस ने सदैव ही चुनाव पूर्व मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया है और यह कांग्रेस का सामान्य सा खेल बन गया है। लोग कांग्रेस की इन चातुर्यपूर्ण चालों को लोग भलीभांति समझते हैं। वर्तमान रूप में फूड सिक्योरिटी बिल में अनेक प्रकार की गलतियां हैं। यदि केन्द्र सरकार सचमुच लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है तो इसे पहले तो छत्तीसगढ़ में चल रहे लोगों को स्वीकार्य फूड सिक्योरिटी सिस्टम को लागू करना चाहिए और तब इसे संसद में पेश करना चाहिए। इस समय कांग्रेस जितनी भी योजनाएं लाई है, जैसे 'मनरेगा', इससे केवल भ्रष्टाचार ही फैला है। अत: मेरा मानना है कि वर्तमान लोकप्रिय योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए कम और राजनैतिक लाभ के लिए ज्यादा बनाई गई हैं।

प्र.: क्या भाजपा यूपीए सरकार की वर्तमान रूप में पेश फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन करेगी?

– हम फूड सिक्योरिटी बिल कानून के पीछे की भावना का समर्थन करते हैं। परन्तु, वर्तमान रूप में इस बिल में कई खामियां हैं। परन्तु यदि बिल का संशोधन छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी मॉडल के आधार पर किया जाता है तो हम इसका समर्थन करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ बिल की सराहना भारत के सुप्रीम कोर्ट और विश्व बैंक ने भी की है।

प्र.: क्या भाजपा एनडीए की संख्या बढ़ाने और अपनी ही ताकत बढ़ाने पर विचार कर रही है? क्या आप समझते है। कि भाजपा के लिए तीसरा मोर्चा कोई चुनौती बन सकता है?

– यदि हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो स्वाभाविक है कि सांझा सहयोगी भी हमारे साथ आएंगे और हम एक स्थिर सरकार दे पाएंगे। हम अब स्वतंत्र रूप से अपने बल पर लड़ने वाली सीटों को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्पष्ट है कि इस बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है और कोई भी अन्य राजनैतिक पार्टी भाजपा के लिए खतरा नहीं बन सकती है। तीसरा मोर्चा एक विफल अनुभव रहा है और यह मिथक है तथा यह सदा ही मिथक बना रहेगा।

प्र.: आप भारत की वर्तमान राजनैतिक स्थिति को कैसा मानते हैं और इसमें भाजपा की क्या भूमिका होगी?

– वर्तमान राजनैतिक स्थिति निश्चय ही भ्रामक है। भारत का आम आदमी कांग्रेसी कुशासन और भ्रष्टाचार से जल्द से जल्द मुक्ति पाने को बेचैन है। भाजपा इस शून्यता को भरने का प्रयास कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें लोगों का पूर्ण समर्थन मिलेगा और हम केन्द्र में सरकार बनाएंगे। भाजपा ने विगत में अच्छा शासन दिया है और भाजपा ही भारत की एक मात्र पार्टी है जो अच्छी और स्थिर सरकार दे सकती है।

प्र.: आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगामी चुनावों के लिए जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं?

– आज भाजपा पर एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वह कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के कुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा में कोताही, वोट-बैंक राजनीति, जबरदस्त भ्रष्टाचार और मुद्रास्फीति का अंत करे, जो गत एक दशक से चला आ रहा है। देश ने यूपीए को सत्ता से उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए हमें कांग्रेस से एकजुट होकर लड़ना होगा ताकि भ्रष्टाचार मुक्त, जनविरोधी शासन से मुक्ति मिल सके और इस महान देश की गरिमा को फिर से बहाल किया जा सके। ■

कांग्रेस के जाने का समय आ गया है : राजनाथ सिंह

गत 11 अगस्त को नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुये दिल्ली भाजपा ने विशाल और ऐतिहासिक "बिजली रैली" आयोजित की और दिल्ली की भ्रष्ट, निकम्मी और असंवेदनशील कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आवाहन किया। पार्टी ने इस बात को पुन: दोहराया कि सत्ता में आने के बाद बिजली की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की जायेगी और लाखों लोगों के समक्ष यह स्पष्ट किया कि ऐसा किस प्रकार किया जायेगा।

सुबह से ही रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा होने लगे थे। जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, रामलीला मैदान की ओर आने वाली सभी सड़कें समर्थकों और पार्टी के साथ सहानुभूति रखने वालों से भर गई। जो भाजपा नेता इस रैली में बोले उन्होंने कांग्रेस के कुशासन का पर्दाफाश किया और यह वादा भी किया कि कांग्रेस द्वारा किये गये गलत फैसलों को भाजपा दिल्ली में सत्ता आने के बाद ठीक करेगी।

इस रैली के प्रति जनता का उत्साह इतना था कि वे दिल्ली के हर कोने से आये और दिल्ली की कांग्रेस सरकार की उदासीनता के विरूद्ध अपना आक्रोश और विरोध व्यक्त किया।

रैली को संबोधित करते हुये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि अब इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता कांग्रेस को विदा करना चाहती है। श्री सिंह ने कहा कि बिजली की दिल्ली में दरों में निरंतर वृद्धि करके जनता को लूटने में कांग्रेस का भी हाथ है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह खेद की बात है कि श्रीमती शीला दीक्षित पिछले 15 वर्षों से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं किन्तु अधिकांश नागरिकों को मूलभूत सुविधायें नहीं मिली हैं। उन्होंने वादा किया कि जब भाजपा सत्ता में आयेगी तो वह सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधायें जैसे कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, समुचित जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध करायेगी।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण और भारतीय सैनिकों की हत्या का जिक्र करते हुये भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के अधीन कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख दिया है। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध के स्तर को घटा दिया जाये और प्रधानमंत्री को अगले महीने अमेरिका में होने वाले संयुक्त राज संघ महासभा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं करनी चाहिये। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि भाजपा संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन करेगी क्योंकि पार्टी यह नहीं चाहती कि कांग्रेस को देश की गरीब जनता का ख्याल न रखने के लिये कोई बहाना मिले। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस की नीति देश में गरीबी को बनाये रखने की है किन्तु वह यह नही जानती कि आज भारत के युवाओं की उनकी प्रतिभा और कठिन परिश्रम के लिये पूरी दुनिया में प्रशंसा की जा रही है।

रैली को संबोधित करते हुये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री विजय गोयल ने वर्तमान कांग्रेस सरकार की असंवेदनशील रवैये की ओर ध्यान आकृष्ट किया। श्री गोयल ने कहा कि पिछले वर्षों दिल्ली में बिजली की दरों में 72 प्रतिशत तक

की वृद्धि करने में बिजली कंपनियों के साथ मिलीभगत करने में कांग्रेस सरकार और बिजली कंपनियों के बीच सांठगांठ रही है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली की दरों में 300 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का अनुमोदन कर दिया है क्योंकि उसने बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित 19,000 करोड़ रूपये की रेगुलेटरी लॉसेज को स्वीकार कर लिया है, जो विधानसभा चुनाव के पश्चात लागू होगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस सरकार और बिजली कंपनियों की योजना को विफल नहीं किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों को इस समय दिये जा रहे बिजली के झटकों के लिये, नुकसान उठाना पड़ेगा।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा तुरंत वे कदम उठायेगी जिससे कि बिजली की दरों में 30 प्रतिशत की कमी हो और बिजली कंपनियों की लूट समाप्त हो। श्री गोयल ने दिल्लीवासियों को याद दिलाया कि जब वर्ष 2002 में बिजली का निजीकरण हुआ था तो बिजली 0 से 50 यूनिट के स्लैब में 1 रूपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध थी और औसत दर 1.37 रू. प्रतियूनिट थी। अब बिजली कम से कम 3.90 रू. प्रति यूनिट दी जा रही है, जो 285 प्रतिशत की वृद्धि है।

"बिजली कंपनियां ऊंचे दरों पर अपने ग्रुप की ही कंपनियों से उपकरण खरीद कर, लेखाओं में गड़बड़ी और हानि दिखाकर अनैतिक कार्य करके जनता को लूट रही है।"

''श्री गोयल ने कहा कि जिस प्रकार मोबाईल, टेलीफोन सेवा में प्रतियोगिता करके कॉल दरें कम हुई उसी प्रकार भाजपा बिजली के क्षेत्र में भी प्रतियोगिता शुरू करवायेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दरें कम हों और उपभोक्ताओं को कम से कम देना पड़े।"

उन्होंने आगे कहा "बिजली क्षेत्र के अतिरिक्त कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आज सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और बच्चों के माता-पिता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सरकार आंकड़ों में गड़बड़ी कर झूठे दावे कर रही है।

"बिजली के निजीकरण के बाद कांग्रेस सरकार पानी का भी निजीकरण करना चाहती है, जबकि आधी दिल्ली अभी भी प्यासी है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव के कुछ ही महीने पहले अनेकों स्कीमों की घोषणा की है जैसे कि लालडोरा क्षेत्र का विस्तार और धारा 81 का सीमित उपयोग। यह सरकार पिछले 15 वर्षों से क्या कर रही थी?" श्री गोयल ने पूछा।

रैली को संबोधित करते हुये दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने कहा "कांग्रेस सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के नाम पर भी एक बड़ा घोटाला किया है। कम से कम 116 ऐसी कालोनियां हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है फिर भी उन्हें नियमित घोषित किया गया है। कांग्रेस के नेता लाखों रूपये डकार गये हैं।"

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन ने कहा "दिल्ली की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है चाहे वह बिजली, पानी, यमुना की सफाई, पर्यायवरण, खाद्य और सिविल सप्लाई, परिवहन का क्षेत्र हो। हमने वर्ष 2003 में ही बिजली घोटाले का मामला उठाया था और कांग्रेस नेता डॉ. एस.सी. वत्स की अध्यक्षता वाली दिल्ली विधानसभा की लोकलेखा समिति ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि बिजली के क्षेत्र में कम से कम 12,500 करोड़ का घोटाला हुआ है।"

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि "जनता कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। हम मुख्यमंत्री को बिजली के क्षेत्र में हुये घोटाले के विषय में बहस करने की चुनौती देते हैं।"

रैली को संबोधित करने वालों में सम्मिलित थीं पूर्व मेयर आरती मेहरा, विजय जॉली, राष्ट्रीय सचिव अनिल जैन, वाणी त्रिपाठी और श्याम जाजू तथा भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती किरन खेर। दिल्ली भाजपा चुनाव प्रभारी श्री नितिन गडकरी हवाई यात्रा में विलंब होने के कारण रैली में उपस्थित नहीं हो सके किन्तु उन्होंने श्री विजय गोयल, अन्य भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को इस रैली को सफल बनाने हेतु बधाई दी। ■

हमारा वादा

1. बिजली दरों में 30 प्रतिशत की कटौती करेंगे।
2. बिजली की खरीद में पारदार्शिता लाएंगे।
3. प्रतिस्पर्धा पर बल।
4. ओपेन एक्सेस प्रणाली लाएंगे।
5. अनावश्यक बिजली खरीद को रोकेंगे।
6. सभी उपभोक्ता को अलग न्यूट्रल उपलब्ध कराएंगे।
7. बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता लाएंगे।
8. बिजली वितरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा देंगे।
9. बिजली की चोरी रोकेंगे।
10. बिजली वितरण कंपनियों को सूचना कानून के अंतर्गत लाएंगे।
11. डीईआरसी में सुधार करेंगे।
12. ऊर्जा आडिट करायेंगे।

पाकिस्तान से कब चुकता करेंगे हिसाब : नरेंद्र मोदी

भाजपा प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दक्षिण भारत में रैली की। गत 11 अगस्त को हैदराबाद में श्री मोदी ने केंद्र की यूपीए सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उलझी केंद्र सरकार के लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना द्वारा 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के मुद्दे पर उन्होंने पीएम से सवाल किया कि आप पाकिस्तान से हिसाब कब चुकता करेंगे?

श्रीमती कहा कि अपनी करतूतों पर यूपीए सरकार चलाने वालों को डूब मरना चाहिए। हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मोदी ने कहा कि देश को कांग्रेस मुक्त बना कर हम एनटीआर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अंत में श्री मोदी ने रैली में उपस्थित लोगों से 'YES WE CAN, YES WE WILL DO' के नारे लगवाए। श्री मोदी की रैली में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये लोग श्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 5 रुपये का टिकट लेकर आए थे। आंध्र भाजपा ने इस रैली का नाम 'नवभारत युवाभेरी' रखा था। हैदराबाद में आयोजित इस 'नवभारत युवाभेरी' में श्री नरेंद्र मोदी ने तेलुगू में अपने भाषण की शुरुआत की। हालांकि, शुरुआती अभिवादन के बाद जल्द ही वह अपने चिर-परिचित अंदाज में हिन्दी में भाषण देने लगे।

श्री मोदी ने कहा, 'कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे जवान का सिर काट लिया था तो देश के पीएम ने कहा था कि ऐसी घटना दोबारा होगी तो हम पाकिस्तान से हिसाब चुकता करेंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने हमारे 5 जवानों को गोलियों से भून दिया है, लेकिन पीएम चुप हैं। ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति में डूबी इस सरकार के लिए देश की सुरक्षा कोई मायने ही नहीं रखती। मैं पूछना चाहता हूं देश के पीएम से कि आपने देशवासियों से जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आप पाकिस्तान से कब हिसाब चुकता करेंगे?'

श्री मोदी ने किश्तवाड़ की हिंसा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, 'किश्तवाड़ सुलग रहा है। न जाने कितने लोग मारे गए हैं। कितनी दुकानों को और कितने घरों को जलाया गया है यह भी नहीं मालूम। जम्मू-कश्मीर की सरकार छुपाना चाहती है। वह कुछ भी नहीं बताना चाहती है। हमारे वरिष्ठ साथी श्री अरुण जेटली जब किश्तवाड़ जाना चाह रहे थे तो उन्हें जम्मू एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। उन्हें किश्तवाड़ नहीं जाने दिया गया। वहां पर राष्ट्र विरोधी ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं और केंद्र की सरकार भी चुपचाप बैठी है।'

श्री मोदी ने कहा, 'देश की सुरक्षा खतरे में है। आज बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ के जवानों को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के

आदेश दिए गए हैं। यहां तक कहा गया है कि अगर घुसपैठिए आक्रमक रवैया अपनाते हैं तो उन्हें बिना किसी दिक्कत के भारत में प्रवेश करने दिया जाए। यही नहीं इटली के सैनिक हमारे निर्दोष मछुवारों की हत्या कर देते हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। यह सब वोट बैंक की राजनीति के लिए दिल्ली की सरकार कर रही है।'

श्री मोदी ने चीनी घुसपैठ के मसले को भी उठाया। उन्होंने कहा, 'चीन की सेना सीमा पार करके देश के अंदर आ गई थी। चीनी सेना तो वापस अपने देश चली गई, लेकिन हमारी सेना को अपने ही देश में पीछे हटना पड़ा। यह दुर्भाग्य की बात है। इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि घटना के बाद बड़ी-बड़ी बातें करने वाले विदेश मंत्री जब चीन गए तो उसे आंख दिखाने की बजाये उसकी बड़ाई की। विदेश मंत्री ने कहा कि पेइचिंग बहुत सुंदर शहर है। मुझे यहीं बस जाने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। डूब मरना चाहिए यूपीए सरकार चलाने वालों को।'

श्री नरेंद्र मोदी ने रैली में आंध्र प्रदेश के बंटवारे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस डिवाइड ऐंड रूल' का सहारा लेकर आज तक राज करती आई है। आंध्र का बंटवारा कर कांग्रेस ने भाई-भाई को लड़वा दिया है। एनडीए सरकार में भी राज्यों का बंटवारा हुआ था। कोई विवाद नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना जरूर बने, लेकिन सीमांध्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर यह बंटवारा करना ही था तो सरकार ने पहले से सीमांध्र के लिए राजधानी बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। अगर यह काम 2004 में किया गया होता तो आज विवाद नहीं होते।'

रैली में श्री मोदी ने आंध्र के सबसे लोकप्रिय नेता रहे एनटीआर को याद किया। उन्होंने कहा कि एनटीआर की मदद से केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन पाई थी। हम इस देश को कांग्रेस मुक्त करके एनटीआर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लंबे समय से कांग्रेस की सरकारें हैं। विकास का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इन्हीं दोनों प्रदेशों में होती हैं। यहीं के किसान सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं।'

श्री नरेंद्र मोदी ने रैली में आए युवाओं का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, 'आप 5 रुपये का टिकट खरीद कर मुझे सुनने आए हैं। टिकट का यह पैसा उत्तराखंड पीड़ितों के लिए भेजा जाएगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के पीड़ितों के साथ आप भी खड़े हैं।'

इसके पहले श्री मोदी जब मंच पर पहुंचे तो उनका स्वागत फूल-मालाओं से किया गया। एयरपोर्ट पर भी श्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इस रैली में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमण, आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जी. किशन रेड्डी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्री विद्यासागर राव सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

भीड़ की यह भाषा, भीड़ का यह भाव, भीड़ का यह प्रेम

✍ गोविन्द मालू

भीड़ की कोई भाषा नहीं होती, भाव की कोई जुबान नहीं होती। वह तो अपने नायक से विश्वास की भाषा में दिल की जुबान से बात कर लेती है। इस रिश्ते को जिसने नहीं समझा उसे राजनीति में अनाड़ी कहा जाना चाहिए। कांग्रेस को यह बात पैंसठ साल तक राजनीति करने के बाद भी समझ नहीं आई है तो यह उसका अपना दुर्भाग्य है। लेकिन भाजपा इस मायने में भाग्यशाली है कि भीड़ की भाषा और उसके भाव की जबान को समझने में निपुण शिवराज सिंह चौहान उसके नायक है और यदि उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रहे अपार जन सैलाब का उनके प्रति अगाध प्रेम कोई माप दंड है, वैसे राजनीति में जनता का यह प्रेम ही सर्वोपरि मापदंड होता है, तो यह बात कांग्रेस को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि शिवराजसिंह चौहान से राजनीति में वह हार चुकी है। भीड़ की भाषा और उसके भाव की जुबान को समझने में शिवराज सिंह जैसा कुशल नेतृत्व उसके पास नहीं है।

प्रदेश की अपनी जनता से सीधे संपर्क करने जन आशीर्वाद यात्रा पर निकला भाजपा का यह जननायक जहाँ से गुजर रहा है एक ही आवाज गूंजती है ' शिवराज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं '। इन्ही समवेत स्वरों में एक जोश भरा नारा सुने देता है, 'शिवराज तुम ही राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं।'' प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की इस जन आशीर्वाद यात्रा में मैं उन्हीं के आदेश और संगठन के निर्देश पर मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी के साथ चल रहा हूं। मैं उनकी पिछली जन आशीर्वाद यात्रा में भी साथ रहा था लेकिन तब और अब में बहुत फर्क आ गया है। जी हाँ, जन जोश पहले से कई गुना अधिक देखने को मिल रहा है। निश्चित ही शिवराज के शासन के अनुकूल परिणामों का यह असर है। भीड़ का भाव पहले से कहीं अधिक भावुक है। इसका सरल अर्थ यह है कि जनता का उनके प्रति लगाव अधिक गहरा गया है। मैं राम जन्म भूमि आन्दोलन में भी सक्रिय रहा था जब भारतीयता का भाव और संस्कार जन विस्फोट के रूप में सामने आया था। लेकिन आप यकीन मानिये कि बीते आठ साल का यह अनुभव बिलकुल भिन्न है। बिना लाग लपेट का, बिना लम्बे चौड़े लेकिन खोखले दावों के केवल अपने काम और भाव के बल पर जन सैलाब का चहेता बना यह नायक सच में बिलकुल भिन्न है।

रात के करीब १-३ बज रहे हैं। दिनभर की यात्रा, और संवाद से थके नेता। उधर जन प्रेम की उर्जा से सराबोर मुख्यमंत्री अब भी कह रहे है कि अधिक से अधिक लोगों से मिल लूं। उन्हें आशा से भर दूं जो कई घंटों से, बारिश के थपेड़ों को सह कर नींद के

झोकों से लड़कर मुझसे (मुख्यमंत्री से) मिलने की आस लेकर यहाँ आये हैं। शाजापुर जिले के शुजालपुर क्षेत्र में अकोदिया मंदी, बोलाई, बोदिगाँव।.... .जहाँ से वे गुजरे लोग इन्तजार करते मिले। बच्चे, बड़े,युवा, बूढ़े स्त्री पुरुष, कहीं-कहीं तो परिवार के परिवार। रात गहरा रही है लेकिन छोटे से गाँव की वह बच्ची किसी अपने के अपने गाँव आने की खांटी भारतीय खुशी के जोश में खुद को नाचने से रोक नहीं पा रही है तय है कि उसके माता पिता माता, भाई-बहन ने ही उस नन्ही लड़की को बताया होगा कि कोई अपना आज अपने गाँव आ रहा है !

इतने दृश्य याद आ रहे हैं कि किसे भूलूं किसे याद करूं। किसे छोड़ दूं, किसे लिख लूं। हर जगह उनके आने की खुशी और मिल लेने का रोमांच।

३१ जुलाई का दिन और रात। जीरापुर से प्रारंभ कुरावर होकर सीहोर में पड़ाव अगले दिन कालापीपल के निकट से चल कर रानोगंज, फुलेन, अकोदिया मंडी, सारंगपुर, बड़ोदीया होकर शाजापुर। लोग मगन होकर मुग्ध होकर मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिलाने, उन्हें देखने के लिए दिन से लेकर देर रात तक पलक बिछाए सड़कों पर बेताब भीड़ की भाषा और प्रेम के भाव का सैलाब लिए डटे थे। क्या है यह? क्या नाम दूं इसे? कैसे शब्दों में बयां कर दूं कि यह शिवराज सिंह नाम के एक इंसान के लिए प्रेम के माधुर्य का विस्फोट था? या सावन की फुहारों के बीच बरस रहा प्यार? कहीं-कहीं इस की धारा मुसलाधार थी तो कहीं बूंदों की अनवरत झड़ी। शिव के माह में इस शिव का अपने आराध्य की आराधना का यह अनुष्ठान लोकतंत्र के भाव का अद्‌भुत दृश्य रचा रहा था। जिस तरह रोमांस में साथ साथ जीने मरने की कसमे खाई जाती है उसी तरह इस जन प्रेम में भी ये कसमें खाना प्रेम की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जरूरी होता है। सामने जनसैलाब था इधर उनका एक नायक। कसमें खाई जा रही थीं, वादे निभाए जा चुके थे आगे साथ रहने का वादा किया जा रहा था।

इस रचना के साक्षी हम देख रहे थे कि क्या तो वृद्ध माताएं, क्या युवा किशोर और क्या बेटियां, पूरी आत्मा के साथ दो घंटे-तीन घंटे विलम्ब से चल रही इस यात्रा के लिए बावजूद की हाथों में पुष्प पंखुडियां लिए खड़ी रही।

22 -23 जुलाई को उज्जैन से महाकाल दर्शन के साथ प्रारंभ इस यात्रा के हर पड़ाव पर भी यही चित्र था। जब अपनी ओजस्वी प्रखर वाणी में शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि अरे भाई किसकी सरकार होगी तो जन भेदी पुकार उठती है भाजपा और अगली बार किसको मुख्यमंत्री बनाओगे तो कह उठती है शिवराज-शिवराज! यह भीड़ लाई नहीं गई थी, स्वयं आई थी। यह कार्यकर्ता नहीं आम जनता थी जो शिवराज-शिवराज पुकार-पुकार कर कह रही थी कि बस अब हमारा यही निर्णय कि शिवराज तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं।

वर्तमान में कुछ विदेशी घटनाएँ टीवी पर देखी, अखबारों में पढ़ीं। जैसे मिस्त्र के तहरीर चौक में क्रांति के मायने थे बदलाव, सत्ता पलट करना। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग है गाँव गाँव में स्वस्फूर्त लोग अपनी ओर से घंटों खड़े रहकर यह वादा कर रहे हैं। सैलाना के पास छोटा सा 8 हजार की आबादी का गाँव। रात 11:30 बजे के लगभग 1200 से 1500 जनता ग्रामीण की जज्बा देखते ही बनता था। मालवा में छेड़ा (घूँघट) निकली हुई महिलाऐं घूँघट की ओट से अपने जननायक की अगवानी कर अचंभित कर देती हैं। रात 1:30 बजे सैलाना की सभा में तो गजब की भीड़ ने वहां खड़े ग्रामीण रामचंद्र ने बताया ''भैया आज तक इतनी रात को ऐसी सभा नहीं देखी'' इससे पहले नागदा में रास्ते-रास्ते वही स्वर "खाली कर दो रास्ते शिवराज जी के वास्ते'' गूंजा।

पड़ाव दर पड़ाव बढ़ता जाता समर्थकों का सैलाब

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे जन समर्थन को प्रत्यक्ष और लगातार देखने के बाद एक बात बहुत साफ साफ समझ में आती है कि यात्रा के लिए जुटने वाली भीड़ में उन नौजवानों की संख्या काफी बड़ी है जो अभी अभी वोटर बने हैं। इन किशोर युवाओं को देख यह भी अहसास होता है कि युवा पीढ़ी भी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है। राजनीति की नजर से यह एक महत्त्वपूर्ण और भाजपा के लिए उत्साह् बढ़ानेवाला तथ्य है। मैं इस यात्रा का मीडिया प्रभारी होने के नाते लगातार साथ चल रहा हूं और गवाह हूँ कि एक के बाद एक इलाके में शिवराज जी को देखने, उनसे मिलने और अपने इस विश्वास को फिर आश्वस्त करने कि उन्होंने जिसे अपना नेता माना है वह उनकी आशा के अनुरूप है, भीड़ बढती जा रही है। राजगढ़ जिला, रतलाम जिला, झाबुआ जिला, मंदसौर जिला, शाजापुर जिला, उज्जैन जिला।..जिस तरफ से भी यह यात्रा गुजर रही है, लोग अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए शिवराज जी के रथ की तरफ बढे चले आ रहे हैं। उस दिन राजस्थान की सीमा

से लगे मंदसौर नीमच जिले के अनेक स्थानों पर एसा मौका भी आया जब सीमा पर के लोगों ने भी आगे आकर शिवराज जी का स्वागत किया, भले ही वे यहाँ के वोटर नहीं थे। गरोठ क्षेत्र से प्रारंभ हुए इस जन आशीर्वाद के कार्यक्रम के कुछ दृश्य में आपके साथ याद करना चाहता हूँ। पूरे रास्ते सड़क किनारे जगह जगह लगे मंचों से स्वागत के बीच कई जगह ऐसा भी हुआ कि काफिले को चलने की जगह तक नहीं मिल रही थी। भीड़ हटने के लिए तैयार नहीं थी। शिवराज जी से मिले बिना कोई वापस जाना नहीं चाहता था। इस वजह से कई बार देरी हुए और तय कार्यक्रम से घंटों देरी से यात्रा नियत स्थानों तक पहुंच सकी। सुवासरा की जनसभा में तो भारी भीड़ जुटी ही, नगर में सड़कों पर दोनों तरफ खड़े लोग फूल हार फेंक कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। एक स्थान पर बोहरा समाज ने बाकायदा अपने परंपरागत बंद के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस स्वागत में महिलाओं ने भी आगे आ कर जताया कि समर्थन और स्नेह के रास्ते में न परंपरा आड़े आती है, न ही रूढ़ियाँ। जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगो की भारी भीड़ ने स्वागत कर इस दुष्प्रचार का करार जवाब दिया कि भाजपा सांप्रदायिक है, वह अल्पसंख्यक विरोधी है। सुवासरा से लेकर आलोट और फिर जावरा तक आते आते आधी रात हो चली थी लेकिन भीड़ की संख्या और जोश में रत्ती भर भी कमी नहीं दिखाई दे रही थी। मानो हरेक इलाका एक दूसरे से यह प्रतिस्पर्धा करने में जुटा हो कि कौन अधिक से अधिक वजनदार स्वागत करता है। उधर शिवराज जी का जोश और उर्जा भी इन समर्थकों के जोश से जरा भी कम नहीं पड़ रही थे। जितना जोरदार स्वागत होता, मुख्यमंत्री शिवराज जी उतने ही अधिक जोश से अभिवादन स्वीकार करते। कई बार तो वे अभिभूत होकर रथ से नीचे उतर पड़ते और समर्थको के बीच पहुँच जाते। ■

(लेखक जनआशीर्वाद यात्रा के मीडिया प्रभारी तथा मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं)

भाजपा महिला मोर्चा ने सरहद पर जवानों को बांधी राखी

गत 21 अगस्त 2013 को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष डा. सरोज पाण्डेय महिला मोर्चा की अन्य पदाधिकारी बहनों के साथ जम्मू के पास भारत पाक सीमा पर सुचेतगढ़ बार्डर पर तैनात जवानों को राखी बांधी। इनके वहां पहुंचने पर सीमा पर तैनात जवान भी प्रफुल्लित हो गये और उन्होंने अपनी बहनों का खुले दिल से स्वागत किया।

सुश्री सरोज पाण्डेय ने चर्चा में कहा कि हमारे देश के वीर जवान

हर मौसम, हर त्यौहार पर लगातार सीमा पर तैनात रहते है और देश की सुरक्षा करते हैं। यह हमारे सैनिक भाई ही है जो सही मायने में हम देश की सभी बहनों की रक्षा करते है। ऐसे में हम बहनों का भी फर्ज बनता है। कि भाईयों को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राखी बांधकर उन्हें यह बतायें कि हमारे मन में भी उनके प्रति कितना सम्मान और प्रेम है।

सुश्री पाण्डेय अपने अन्य साथी बहनों के साथ इन सैनिकों के पास राखी बांधने पहुंची तो वहां पर कुछ देर के लिए वातावरण भावनात्मक हो गया था। कदाचित जवानों को भी अपने - अपने घरों में उनका इंतजार करती बहनों की याद आयी होगी। सुश्री पाण्डेय ने भी भावविभोर होकर कहा कि यह क्षण भी उनके जीवन का यादगार क्षण है जब वह सरहद पर अपने सौनिक भाईयों को राखी बांधने आयी है।

इस कार्यक्रम में उनके साथ महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दर्शना दजदोश, सांसद गुजरात, श्रीमती जयश्री बेन पटेल, सांसद गुजरात, श्रीमती रमा देवी, सांसद, बिहार, श्रीमती लतिका शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा, श्रीमती रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री, महिला मोर्चा, श्रीमती आशा जैसवाल, राष्ट्रीय मंत्री, महिला मोर्चा एवं श्रीमती प्रिया सेठी, प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर सहित भारी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित थी। ■